● वर्ष-5

● अंक-157

रायपुर, शनिवार
14 फरवरी 2026

● पृष्ठ-8

● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8› छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैण्ड ...

आज हम नया इतिहास बनते हुए देख रहे हैं...

सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन का उद्घाटन कर बोले प्रधानमंत्री मोदी

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सेवा तीर्थ का उद्घाटन किया, जो एक नई इमारत है जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय स्थित हैं। केंद्र ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि नई इमारतें भारत की प्रशासनिक शासन संरचना को दर्शाती हैं और आधुनिक, कुशल, सुलभ और नागरिक-केंद्रित शासन प्रणाली के निर्माण के लिए प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करती हैं।

दशकों से, मंत्रालय सेंट्रल विस्टा में बिखरे हुए पुराने भवनों से काम करते रहे, जिसके कारण समन्वय में कमी, रसद संबंधी बाधाएँ और रखरखाव की उच्च लागत जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं। नए परिसरों का उद्देश्य निर्बाध समन्वय के लिए डिज़ाइन किए गए भविष्य के लिए तैयार बुनियादी ढांचे में प्रमुख प्रशासनिक विभागों को एक साथ लाकर इन समस्याओं का समाधान करना है। सरकार को उम्मीद है कि इस एकीकरण से निर्णय लेने की प्रक्रिया में तेजी आएगी, लागत कम होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी।

सेवा तीर्थ में तीन प्रमुख कार्यकारी संस्थान - प्रधानमंत्री कार्यालय (सेवा तीर्थ-1), राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (सेवा तीर्थ-2) और मंत्रिमंडल सचिवालय (सेवा तीर्थ-3) - एक ही स्थान पर होंगे, जो पहले अलग-अलग स्थानों से कार्य करते थे। इनके एक ही स्थान पर होने से सरकार के उच्चतम स्तर पर रणनीतिक समन्वय मजबूत होने की उम्मीद है। कर्तव्य भवन-1 और 2 में वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कॉर्पोरेट मामले, शिक्षा, संस्कृति, विधि एवं न्याय, सूचना एवं प्रसारण, कृषि एवं किसान कल्याण, रसायन एवं उर्वरक एवं जनजातीय मामलों सहित प्रमुख मंत्रालयों के कार्यालय होंगे। इस समेकन का उद्देश्य अंतर-मंत्रालयी समन्वय को सुधारना और जनता की पहुंच को सुगम बनाना है।

नए परिसरों में डिजिटल रूप से एकीकृत कार्यालय, सुव्यवस्थित सार्वजनिक संपर्क क्षेत्र और केंद्रीकृत स्वागत सुविधाएं हैं, जो दक्षता और नागरिक सहभागिता को बेहतर बनाने में सहायक हैं। उन्नत डिजिटल अवसंरचना से ई-गवर्नेंस और पारदर्शी प्रशासन को समर्थन मिलने की उम्मीद है।

4-स्टार जीआरआईएचए मानकों के अनुसार निर्मित इन परिसरों में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियां, जल संरक्षण उपाय, अपशिष्ट प्रबंधन समाधान और ऊर्जा-कुशल भवन डिजाइन शामिल हैं। पीएमओ के अनुसार, ये उपाय परिचालन प्रदर्शन में सुधार करते हुए पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हैं।

हंगामेदार रहा बजट सत्र, 9 मार्च तक स्थगित

नईदिल्ली। भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते और पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे के संस्मरण से जुड़े विवाद को लेकर कई दिनों तक चले तीखे राजनीतिक वाद-विवाद के बाद शुक्रवार को बजट सत्र का पहला चरण समाप्त हो गया। यह विवाद संसद के बाहर भी चर्चा का विषय बना रहा। लोकसभा में आज केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका दोनों सदन अब तीन सप्ताह के अवकाश पर चले गए हैं। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही 9 मार्च को फिर से शुरू होगी। बजट सत्र, जो 28 जनवरी को राष्ट्रपति के संसद को दिए गए संयुक्त संबोधन के साथ शुरू हुआ था, 65 दिनों में 30 बैठकों के साथ समाप्त होगा। मध्यावधि अवकाश के दौरान स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अनुदान अनुरोधों की जांच करेंगी। लोकसभा में दो फरवरी से राष्ट्रपति अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। धन्यवाद प्रस्ताव और इसका समर्थन करने के लिए भाजपा के दो सदस्यों

के भाषण के बाद जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपनी बात रखनी शुरू की तो उनकी एक टिप्पणी को लेकर सदन में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के कारण चर्चा नहीं हुई और न ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का इस पर जवाब हो सका। हालांकि लोकसभा में इस सप्ताह आम बजट पर चर्चा हुई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को इसका जवाब दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सदन में बोलने की अनुमति नहीं देने और आठ विपक्षी सांसदों को निलंबित करने के मामले में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के प्रस्ताव के लिए लोकसभा महासचिव को एक नोटिस दिया है।

सूत्रों ने कहा कि नोटिस बजट सत्र के द्वितीय चरण की शुरुआत होने पर विचार के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। उच्च सदन में भी 2 फरवरी से राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। इस चर्चा का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पांच फरवरी को जवाब दिया था। राज्यसभा में नौ मार्च से आम बजट 2026-27 पर चर्चा शुरू हुई थी जिसका जवाब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 फरवरी को दिया। कल ही उच्च सदन में औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित किया गया था।

आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह ने शुक्रवार को राज्यसभा में सरकार से मांग की कि थल सेना में भर्ती के लिए परीक्षा पास कर चुके युवाओं की तत्काल भर्ती की जाए और सैनिकों को वरिष्ठ अधिकारियों की सेवा में लगाना बंद किया जाए। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए सिंह ने कहा कि 2019 से 2022 के बीच लगभग 1.23 लाख युवाओं ने थल सेना में भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा परीक्षा पास की, जबकि लगभग 7,000 उम्मीदवारों ने वायुसेना के लिए परीक्षा उत्तीर्ण की।

राज्यसभा में भाषण के अंश हटाने पर भड़के कांग्रेस अध्यक्ष खरगे

राज्यसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शुक्रवार को कहा कि 4 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान दिए गए उनके भाषण का एक बड़ा हिस्सा बिना किसी औचित्य के आधिकारिक अभिलेख से हटा दिया गया। खरगे ने इस कदम को लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के विरुद्ध बताया और कहा कि हटाए गए अंशों में सरकार की नीतियों की उनकी आलोचनाएं शामिल थीं, जिन्हें विपक्ष के सदस्य के रूप में उजागर करना उनका कर्तव्य है। उन्होंने हटाए गए अंशों को बहाल करने का भी आग्रह किया।

संसद के उच्च सदन में बोलते हुए खरगे ने कहा कि 4 फरवरी, 2026 को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा के दौरान मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूँ। जब मैंने राज्यसभा की वेबसाइट पर अपलोड किया गया वीडियो देखा, तो मैंने पाया कि मेरे भाषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बिना किसी उचित स्पष्टीकरण या औचित्य के हटा दिया गया है। समीक्षा करने पर मैंने पाया कि हटाए गए हिस्से में संसद में वर्तमान सरकार के कामकाज पर मेरी टिप्पणियाँ और तथ्यात्मक संदर्भ शामिल थे। मैंने प्रधानमंत्री की कुछ नीतियों की आलोचना भी की, जो विपक्ष के सदस्य के रूप में मेरा कर्तव्य है, विशेषकर तब जब ये नीतियाँ जनता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती प्रतीत होती हैं।

भारत स्वतंत्र रूप से काम के लिए तैयार रहेः चौहान

नई दिल्ली। भारत के मौजूदा सर्वोच्च सैन्य अधिकारी जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में स्थायी दोस्त या स्थायी दुश्मन जैसी धारणाएं भरोसेमंद नहीं होतीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को हर परिस्थिति में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वे पुणे में दक्षिणी कमान द्वारा आयोजित 'जेएआई' (जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन) सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।

रणनीतिक स्वायत्तता पर जोर

जनरल चौहान ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में किसी भी देश के साथ संबंध स्थायी नहीं होते। परिस्थितियों और राष्ट्रीय हितों के अनुसार नीतियां बदलती रहती हैं। ऐसे में भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए निर्णय लेने चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की सुरक्षा और विदेश नीति का आधार राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होना चाहिए। किसी भी गठबंधन या साझेदारी को इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए।

वैश्विक सुरक्षा माहौल में तेज बदलाव

सीडीएस ने संकेत दिया कि वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और अनिश्चितता बढ़ रही है। उन्होंने आक्रामक राष्ट्रवाद और आर्थिक हथियारकरण का जिक्र करते हुए कहा कि आज व्यापार, सप्लाई चेन, तकनीक तक पहुंच और महत्वपूर्ण संसाधनों का इस्तेमाल रणनीतिक दबाव बनाने के साधन के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता जैसे स्थापित सिद्धांतों को चुनौती दी जा रही है। लंबी दूरी और सटीक मारक क्षमता वाले हथियारों के विकास ने बल प्रयोग की दहलीज को भी कम कर दिया है। जनरल चौहान ने कहा कि औपचारिक रूप से घोषित युद्ध अब कम होते जा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा अब प्रॉक्सी युद्ध, सीमित स्तर के ऑपरेशन और साइबर गतिविधियों के जरिए दिखाई दे रही है। उन्होंने आगाह किया कि सूचना और संज्ञानात्मक युद्ध अब प्रमुख युद्धक्षेत्र बन चुका है, जहां लक्ष्य केवल सेनाएं नहीं, बल्कि पूरा समाज होता है।सेमिनार की थीम 'जेएआई से विजय' पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि रणनीतिक सिद्धांत है, जो उद्देश्य और परिणाम के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। उन्होंने बताया कि 'जेएआई ' का अर्थ है- जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और नवाचार। भविष्य की तैयारी इस बात पर निर्भर करेगी। कि हम अपनी रणनीतिक कमजोरियों, पुरानी सैन्य अवधारणाओं और संगठनात्मक अलगाव को कितनी जल्दी दूर कर पाते हैं।सीडीएस ने कहा कि विजय केवल भाषणों से नहीं, बल्कि ठोस और प्रमाणित परिणामों से परिभाषित होती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आने वाला दशक प्रतिस्पर्धा, टकराव और तकनीकी बदलावों से भरा होगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दौरान मैनपाट में पर्यटन के विकास हेतु 1 करोड़ रुपए तथा सीतापुर में सर्व सुविधायुक्त बस स्टैंड के निर्माण हेतु घोषणा भी की। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सरगुजा जिले में 523 करोड़ 20 लाख 53 हजार रूपए की राशि के 109 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने समारोह को

प्रमुख समाचार

बांग्लादेश को भारत की जरूरतः तारिक रहमान

बांग्लादेश । बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) को मिली बंपर जीत के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि, क्या भारत और बांग्लादेश से रिश्ते सुधरेंगे? क्या भारत से बिगड़े रिश्ते सुधारेंगे तारिक रहमान? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि, शेख हसीना के तख्तापटल के बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में कड़वाहट आई है। कार्यवाहक सरकार के

मुखिया रहे मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान और चीन से दोस्ती बढ़ाई, लेकिन भारत से रिश्ते बेहतर करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया। शेख हसीना की पार्टी पर लगे प्रतिबंध और बिगड़ते रिश्तों के बीच बीएनपी की जीत भारत के लिए राहतभरी खबर है। पीएम मोदी ने बीएनपी के प्रमुख तारिक रहमान को जीत की बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि यह जीत बांग्लादेश के लोगों के उनके नेतृत्व में भरोसे को दिखाती है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के समर्थन में हमेशा खड़ा रहेगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने भारत और बांग्लादेश के रिश्ते को लेकर भी अपनी बड़ा संकेत दिया।

एनसीपी से मजबूर होकर अलग हुए थे अजित पवारः शशिकांत

मुंबई । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के महाराष्ट्र अध्यक्ष शशिकांत शिंदे ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि दिवंगत अजित पवार को अदृश्य ताकतों, धमकियों और झूठे आरोपों के जाल के कारण मूल एनसीपी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। फरवरी 2026 के पार्टी मुखपत्र राष्ट्रवादी में प्रकाशित श्रद्धांजलि लेख में शिंदे ने कहा कि बीते चार-पांच महीनों से पिछली

गलतियों को सुधारने की प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही थी और दोनों गुटों के विलय की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी थी।शिंदे ने दावा किया कि हाल के नगर निगम और जिला परिषद चुनाव अभियानों में अजित पवार की सक्रिय भूमिका उनके घर वापसी के संकेत के रूप में देखी जा रही थी। हालांकि, शिंदे के अदृश्य ताकतों वाले बयान पर एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने आपत्ति जताई। तटकरे ने कहा कि अजित पवार 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के पक्ष में थे और उनका मानना था कि इससे राजनीतिक स्थिरता और बेहतर शासन संभव होगा। उन्होंने यह भी दोहराया कि एनसीपी, एनडीए गठबंधन का हिस्सा है ।

केरल चुनाव : भाजपा और कांग्रेस जल्द जारी करेंगी पहली सूची

तिरुवनंतपुरम। केरल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों ने संकेत दिए हैं कि वे इस महीने के अंत तक अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती हैं। चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले शुरुआती बढ़त लेने के लिहाज से यह सूची बेहद अहम मानी जा रही है।कांग्रेस के भीतर

संगठनात्मक फेरबदल और चुनावी रणनीति समानांतर रूप से चल रही है। केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ अपने गृह जिले कन्नूर के पेरावूर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। यदि वे चुनाव मैदान में उतरते हैं तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना होगा। ऐसे में पार्टी को अंतरिम अध्यक्ष की नियुक्ति करनी पड़ेगी।सूत्रों के अनुसार, केरल के सामाजिक और सांप्रदायिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए अंतरिम अध्यक्ष किसी ईसाई नेता को बनाया जा सकता है। इस पद के लिए केसी जोसेफ और सांसद बेनी बेहनन के नामों पर चर्चा चल रही है। हालांकि, हाल में बेहनन को घोषणापत्र समिति का अध्यक्ष बनाए जाने के बाद केसी जोसेफ का नाम मजबूत माना जा रहा है।

अधिसूचना वापस ले, अनिवार्य करना सही नहीं: इमरान रशादी

नईदिल्ली। केंद्र सरकार ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत वंदे मातरम को राष्ट्रगान जन-गण-मन की तरह ही सम्मान देना अनिवार्य कर दिया गया है। नए प्रोटोकॉल के तहत सभी सरकारी कार्यक्रमों में राष्ट्रगीत के सभी छह छंद बजाए या गाए जाएंगे। इसी बीच वंदे मातरम गायन को लेकर केंद्र सरकार की

गाइडलाइंस के खिलाफ विरोध जारी है। मौलाना मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां हमारी धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ हैं। बेंगलुरु में आईएएनएस से बातचीत में मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि देखिए, भारत एक सेक्युलर देश है और भारतीय संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को मानने और उसका पालन करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए, यदि हमारे गैर-मुस्लिम भाई वंदे मातरम गाते हैं, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मुसलमान होने के नाते हमारी मान्यताओं के अनुसार, इस गीत में कुछ देवी-देवताओं का जिक्र है, जिस कारण हमारे बुजुर्गों ने इसे हमारे लिए मुनासिब नहीं माना।

आरजेडी सांसदों ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन

नई दिल्ल। राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के सांसदों ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफा देने की मांग कर रहे हैं। संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे सांसदों ने केंद्र सरकार से आरक्षण नीति में बदलाव की भी अपील की। वे अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी), अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और अत्यंत पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के लिए 65 प्रतिशत आरक्षण लागू करने और इसे संविधान की नौवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आरजेडी सांसदों का यह प्रदर्शन संसद में जारी आरक्षण और सामाजिक न्याय संबंधी बहसों में नया तनाव पैदा कर रहा है। इस मामले में गतिरोध जारी है और आरजेडी सांसद प्रदर्शन कर अपनी मांग रख रहे हैं।

उम्मीदें धुंधली ही हैं

बांग्लादेश की चुनावी परीक्षा, क्या लौट पाएगा लोकतंत्र का विश्वास?

जाहिद हुसैन

डेढ़ साल पहले, बांग्लादेश को देखकर ऐसा लग रहा था, मानो वह लोकतांत्रिक पतन के वैश्विक दौर को चुनौती देने की राह पर है। आर्थिक निराशा से जूझ रही युवा पीढ़ी के नेतृत्व में हुए व्यापक जन-प्रदर्शनों ने पांच अगस्त, 2024 को शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका। यह इस बात का प्रमाण था कि जहां भी लोकतंत्र दबाव में आता है, वहां के नागरिक एकजुट होकर निरंकुश सत्ताओं को उखाड़ फेंक सकते हैं और व्यवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। कल हुआ राष्ट्रीय मतदान बांग्लादेश के राजनीतिक बदलाव की पहली चुनावी परीक्षा जरूर था, पर लोकतांत्रिक पुनरुत्थान की उम्मीदें अब भी धुंधली ही नजर आ रही हैं।

हसीना की विदाई के बाद देश में लगातार हिंसा, नौकरशाही और औद्योगिक हड़तालों, बाधा उत्पन्न करने वाले प्रदर्शनों और राजनीतिक अनिश्चितता का दौर शुरू हो गया। इसने एक कड़वी हकीकत को उजागर किया कि जब लोकतंत्र को संभालने वाली संस्थाएं खोखली हो जाती हैं, तो लोकतांत्रिक पुनर्निर्माण आसान नहीं होता। आज बांग्लादेश इसी जटिल सच्चाई का जीवंत उदाहरण बन चुका है। 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों से बांग्लादेश की राजनीति दो प्रभावशाली महिलाओं-अवामी लीग की नेता शेख हसीना और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की खालिदा जिया की तीखी प्रतिद्वंद्विता के इर्द-गिर्द घूमती रही। दोनों नेताओं और उनकी पार्टियों के बीच चुनावी मैदान में वर्षों तक कड़वी लड़ाई चलती रही। इस कड़वाहट के बावजूद, देश में सत्ता का हस्तांतरण काफी हद तक शांतिपूर्ण रहा। इसका श्रेय उन 'गैर-पक्षपाती अंतरिम प्रशासन' को जाता है, जो चुनाव कराने व सत्ता की बागडोर सौंपने के लिए अस्थायी रूप से कमान संभालते थे। लेकिन 2011 में, जब शेख हसीना का शासन ज्यादा केंद्रीकृत और सत्तावादी स्वरूप लेने लगा, तो इसे समाप्त कर दिया गया। इसके बाद चुनावी अनियमितताओं और विवादित जनादेशों का सिलसिला शुरू हुआ। भाई-भतीजावाद व कथित भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी होती गईं, और सत्ता ने अदालतों, पुलिस और अन्य सरकारी संस्थाओं का इस्तेमाल

विरोधियों को डराने-धमकाने के लिए करना शुरू कर दिया। बांग्लादेशी नागरिकों को उम्मीद थी कि 2024 के जन-आंदोलन से देश में स्थिरता और जवाबदेही की नई सुबह होगी। शुरुआती उम्मीदों की एक बड़ी वजह नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का नेतृत्व सौंपना था। इससे यह विश्वास जगा कि शायद बांग्लादेश लोकतंत्र, पारदर्शिता और संस्थागत मजबूती की दिशा में नई शुरुआत कर सकेगा। लेकिन यूनुस देश में शांति व अनुशासन बहाल करने के लिए जूझते नजर आए। पुलिस और अदालतों जैसी अहम संस्थाओं पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने में भी वह सफल नहीं हो सके। उधर, क्रांति के बाद से बढ़ती महंगाई, कमजोर वेतन वृद्धि और अन्य आर्थिक दबावों ने आम परिवारों की कमर तोड़ दी। चुनाव की साख पर पहले ही सवालिया निशान लग चुके थे।

राजनीतिक हिंसा, वोट खरीदने के आरोप, अन्य अनियमितताएं और अवामी लीग की भागीदारी पर लगा प्रतिबंध इसकी निष्पक्षता को संदिग्ध बना रहे हैं। फिर भी, इस चुनावी दौड़ में फिलहाल खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान के नेतृत्व वाली बीएनपी सबसे आगे नजर आ रही है। हालांकि, नतीजों का अंदाजा लगाना अभी बेहद मुश्किल है। इस बार करीब 43 प्रतिशत मतदाता 18 से 37 वर्ष के बीच की उम्र के हैं। यह युवा वर्ग अतीत की दलगत दुश्मनियों से अधिक कानून-व्यवस्था, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और निष्पक्ष शासन जैसे व्यावहारिक मुद्दों को लेकर उत्साहित है। ऐसे में, यह पीढ़ी बांग्लादेश के लोकतांत्रिक भविष्य की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है।इस पूरी राजनीतिक तस्वीर में इस्लामी ताकतें एक और अप्रत्याशित कारक बनकर उभरी हैं।

मुस्लिम बहुल बांग्लादेश में इन ताकतों को लंबे समय तक हाशिये पर रखा गया था। पर इन ताकतों ने मौजूदा राजनीतिक व संस्थागत शून्य का भरपूर फायदा उठाया और वे अब कहीं अधिक मुखर हैं। इसके अलावा, एक चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार, पहली बार के मतदाताओं (37 प्रतिशत) की योजना जमात-ए-इस्लामी पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देने की थी। इस पार्टी ने अपनी मजबूत संगठनात्मक क्षमता तथा दो प्रमुख दलों की साख गिरने के बीच खुद को विकल्प के रूप में पेश किया है।

चुनाव का एक और अहम पहलू है-नए राष्ट्रीय चार्टर पर जनमत-संग्रह। इसमें निष्पक्ष चुनावों की गारंटी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कार्यपालिका की शक्तियों पर स्पष्ट सीमाएं तय करने की प्रतिबद्धता को औपचारिक रूप देने की बात कही गई है। यह मुल्क के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए निर्णायक साबित हो सकता है।

500 के नकली नोट फागुन मेले में पहुंचने की खबर

- दंतेवाड़ा एएसपी आर के वर्मा ने कहा, पुलिस को सूत्रों से पता चला है कि नकली नोट यहां खपाने की कोशिश हो रही है.

दंतेवाड़ा। एएसपी आर के वर्मा ने कहा है कि विश्व प्रसिद्ध फागुन मेले में भोले भाले आदिवासियों को ठगने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोग नकली नोट मेले में खपाने की कोशिश कर रही हैं। एएसपी ने कहा कि सूत्रों के जरिए उनको ये जानकारी मिली है। एएसपी ने ये भी बताया कि अभी तक नकली नोट मिलने या पकड़े जाने की कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, न ही किसी ने इस संबंध में कहीं कोई शिकायत दर्ज कराई है। दंतेवाड़ा पुलिस ने बताया कि सूत्रों से मिली जानकारी को गंभीरता से लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। एएसपी ने कहा कि शिकायत मिलती है, तो जांच के लिए एक विशेष एसआईटी गठित की जाएगी, जो इस मामले की जांच करेगी। पुलिस ने दावा किया कि अगर नकली नोट के स्रोत का पता चलता है, तो संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। एएसपी आर के वर्मा ने कहा कि जिले के सभी दुकानदारों को सतर्क रहने और जागरूक करने का काम भी किया जा रहा है। दंतेवाड़ा पुलिस ने अपील करते हुए कहा कि दुकान पर पैसे लेते वक्त दुकानदार अतिरिक्त सावधानी बरतें। बिना नोट की जांच किए नहीं लें। इसके साथ ही कोई भी संदिग्ध शख्स अगर किसी को नजर आए, तो तुरंत पुलिस को खबर दें। पुलिस ने कहा कि हम हर छोटी बड़ी इनपुट को गंभीरता से ले रहे हैं। दंतेवाड़ा पुलिस ने बताया कि नकली नोटों के बाजार में आने से न सिर्फ हमारी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचती है, बल्कि बाजार में नकली नोटों के चलने से दुकानदारों को भी नुकसान होता है। इसके साथ ही लोग बड़े नोट लेने से डरने लगते हैं। पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे नकली नोट मिलने की स्थिति में तुरंत नजदीकी थाने में जानकारी दें, ताकि समय रहते आरोपियों पर कार्रवाई की जा सके। पुलिस ने आश्वासन दिया कि इस मामले में होने वाली सभी आगे की कार्रवाईयों को लेकर समय-समय पर जानकारियां सार्वजनिक की जाएंगी, ताकि नागरिकों को सही और सटीक जानकारी मिलती रहे।

500 रुपये के नकली नोटों की पहचान

नकली नोटों की पहचान करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने असली 500 रुपये के नोटों की पहचान करने में मदद करने के लिए कुछ टिप्स दिए हैं। साइज- मूल नोट का आकार 66 मिमी × 150 मिमी है। डिनॉमिनेशन- 500 देवनागरी लिपि में मुद्रित है। चित्र- महात्मा गांधी का चित्र बीच में प्रमुखता से प्रदर्शित है।

माइक्रो लेटर- भारत और INDIA शब्द सूक्ष्म अक्षरों में लिखे गए हैं। सुरक्षा धागा- रंग बदलने वाला सुरक्षा धागा तिरछा करने पर हरे से नीले रंग में बदल जाता है। वॉटरमार्क- प्रकाश के सामने रखने पर गांधी के चित्र और इलेक्ट्रोटाइप 500 का वॉटरमार्क दिखाई देता है। रंग बदलने वाली स्याही- नोट पर नीचे दाईं ओर 500 रुपये के चिह्न तिरछा करने पर हरे से नीले रंग में बदल जाते हैं। अशोक स्तंभ- अशोक स्तंभ का प्रतीक दाईं ओर मौजूद है। स्वच्छ भारत लोगो- स्वच्छ भारत लोगो और नारा नोट पर छपा हुआ है।

साय सरकार में आरम्भ हुआ बस्तर में शांति की वापसी का स्वर्णिम अध्याय

बस्तर। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग एक लंबे समय तक नक्सल हिंसा की पीड़ा से कराहता रहा। घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों से घिरे इस क्षेत्र ने दशकों तक भय, असुरक्षा और विकास के अभाव को झेला है। परंतु आज वही बस्तर एक नए युग की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन यह परिवर्तन आकस्मिक नहीं हुआ है, इसके लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति, संवेदनशील प्रशासन और सुरक्षा बलों के समन्वित प्रयासों का बड़ा योगदान है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अगुवाई में छत्तीसगढ़ सरकार ने जिस दृढ़ता और दूरदृष्टि के साथ नक्सल समस्या के समाधान की दिशा में कदम उठाया हैं, वह न केवल बस्तर बल्कि पूरे राज्य के लिए आस का दीप बना हुआ है।

देश के राष्ट्रीय पर्वों पर बस्तर संभाग के धुर नक्सल प्रभावित 29 गांवों में आजादी के बाद पहली बार ध्वजारोहण का होना एक औपचारिक आयोजन नहीं बल्कि लोकतंत्र की वास्तविक विजय का प्रतीक बन रहा है। नक्सल के इन गढ़ों में वर्षों तक जहाँ तिरंगा फहराना भी चुनौती था वहाँ अब राष्ट्रीय ध्वज गर्व से लहराता है। यह दृश्य हर छत्तीसगढ़वासी के हृदय में आत्मिक संतोष और गर्व की अनुभूति कराने वाला है। यह सब तभी संभव हो पाया है जब छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा सुरक्षा शिविरों की स्थापना, सड़क और संचार नेटवर्क के विस्तार और प्रशासन की सीधी पहुँच बनाई गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्पष्ट संकल्प के अनुरूप राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर में सुरक्षा, विकास और विश्वास पर आधारित नीति लागू की। इसका परिणाम अब साफ़ दिखाई दे रहा है। सुकमा जिले में 64 लाख रुपए के इनामी 26 हार्डकोर माओवादियों, जिनमें 7 महिलाएँ भी शामिल थीं, इनका आत्मसमर्पण इस परिवर्तन की सशक्त मिसाल बनी हुई है। इस सफलता को सुरक्षा बलों की सफलता नहीं बल्कि मानवीय संवाद और विश्वास की जीत है मानी जा सकती है। मुख्यमंत्री साय ने इसे मानवता की विजय बताते हुए हिंसा का मार्ग त्यागने वालों के लिए सम्मानजनक पुनर्वास का आश्वासन दिया। पुनर्वास से पुनर्जीवन कार्यक्रम में 210 नक्सलियों का एक साथ आत्मसमर्पण करना एक ऐतिहासिक घटना रही। मुख्यमंत्री ने इसे अपने जीवन का सबसे संतोषजनक क्षण बताया। नक्सलवादी आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति 2025 और नियद नेल्ला नार योजना जैसी शुरुआत ने उन युवाओं के जीवन में नई उम्मीद जगाई है जो भ्रमित होकर हिंसा के रास्ते पर चले गए थे। डेढ़ वर्ष के भीतर 435 नक्सली मुठभेड़ों में मारे गए, 1,432 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया और 1,457 नक्सलियों की गिरफ्तारी इस बात का संकेत है कि बस्तर में नक्सलवाद अब अपनी अंतिम साँसें गिन रहा है। माओवादी संगठन के शीर्ष नेता बसवराजू का न्यूट्रलाइज होना और करेंगुड़ा में 31 नक्सलियों का मारा जाना नक्सल आतंक की विदाई मानी जा रही है।राज्य के मुख्यमंत्री साय का लक्ष्य मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाना है।नक्सलवाद उन्मूलन का अभियान जिस गति से चल रहा है राज्य के मुखिया का लक्ष्य अब दूर नहीं प्रतीत होता। बस्तर में परिवर्तन केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है। बस्तर के सुदूर अंचलों तक भी अब विकास की धारा पहुँच रही है। अबूझमाड़ के दूरस्थ गांव रेकावाया में पहली बार स्कूल का निर्माण किया जा रहा है। हिंसा के कारण बंद पड़े लगभग 50 स्कूल फिर से खोले गए हैं।

अपशिष्ट से फसल खराब होने पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा

मक्का प्लांट में घुसकर की तोड़-फोड़,

कोंडागांव। जिले के कोकोड़ी गांव में स्थित मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण प्लांट में देर रात ग्रामीणों ने घुसकर जमकर हंगामा किया। आक्रोशित ग्रामीणों ने प्लांट परिसर में खड़ी कार, ट्रैक्टर सहित कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। घटना में प्रारंभिक तौर पर 10 से 20 लाख रुपये तक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। सूचना मिलते ही छत्तीसगढ़ पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। कोंडागांव के एसपी, एसडीएम सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। एहतियातन क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। हालांकि गांव में अभी भी तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि मक्का प्लांट से निकलने वाला तरल अपशिष्ट (वेस्ट) उनके खेतों तक पहुंच रहा है, जिससे फसलें खराब हो रही हैं। किसानों का कहना है कि वे लंबे समय से प्रशासन को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी शिकायतों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसी नाराजगी के चलते ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से प्लांट का घेराव कर दिया। बताया जा रहा है कि रातभर गांव के लोगों ने प्लांट को चारों ओर से घेर रखा। बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। एक वाहन चालक को जान बचाने के लिए रातभर जंगल में छिपकर रहना पड़ा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कुछ समय के लिए पुलिस बल को भी पीछे हटना पड़ा।

ग्रामीणों ने प्लांट के एमडी विनोद खन्ना पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि प्रबंधन की लापरवाही और नियमित निगरानी के अभाव में समस्या बढ़ती गई।

पकड़े गए गजब के ठगबाज

सूरजपुर। अजब-गजब ठगी का एक मामला बसदेई थाना इलाके से सामने आया है। पुलिस ने ठगी की शिकायत मिलने के बाद दो आरोपियों की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से की है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी नेपाल के बार्डर एरिया से हुई है। पकड़े गए दोनों बदमाशों पर आरोप है कि ये लोग खुद को कभी जेल अधीक्षक बताते थे, तो कभी खुद को किसी थाने का इंचार्ज।

जेल अधीक्षक और थाना प्रभारी बनकर पहले तो ये लोगों को डारते धमकाते, फिर दबिश में लेकर उनसे ठगी की वारदात को अंजाम देते। लोग जब तक उनको समझ पाते ये पैसे लेकर रफूचक्कर हो जाते। फरियादी के मुताबिक आरोपियों ने जेल में बंद उसके बेटे को छुड़ाने के लिए 75 हजार की रकम वसूल ली। ये पूरी ठगी की वारताद और पैसों की वसूली ऑनलाइन की गई। पीड़ित ने बताया कि उसके बेटे को पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। बेटे के गिरफ्तारी से पूरा परिवार परेशान है। परिवार के लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनका बेटा छूट जाए। इसी दौरान आरोपियों ने पीड़ित परिवार से संपर्क किया। संपर्क करने वालों ने बताया कि वो संबंधित थाने का इंचार्ज है जिसमें उसके बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई है। आरोपियों में से एक ने खुद को जेल अधीक्षक भी बताया।

दोनों पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि उनके बेटे कि रिहाई ये लोग करा देंगे। बदले में उनको कीमत चुकानी होगी। 75 हजार में डील फाइनल हुई। आरोपियों ने सुनियोजित तरीके से पीड़ित को झांसे में लिया और ऑनलाइन माध्यम से 75 हजार ट्रांसफर करवा लिए। पैसे जमा होने के बाद जब आरोपियों ने संपर्क बंद कर दिया, तब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद उसने बसदेई थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम गठित की गई।

महासमुंद जिला अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही, अग्निशमन यंत्रों की वैधता समाप्त, आग लगी तो बुझेगी कैसे

- महासमुंद जिला अस्पताल में प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है. अग्निशमन यंत्रों की वैधता समाप्त होने के बाद भी रिफिलिंग नहीं की गई है.

महासमुंद। महासमुंद जिले के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध जिला अस्पताल में आग लगने पर सुरक्षा के लिए छोटे-छोटे अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं.लेकिन इन अग्निशमन यंत्रों की वैधता समाप्त हो चुकी है। यदि अस्पताल परिसर में कहीं भी आग लगी तो इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर भी अस्पताल की दीवारों में अग्निशमन यंत्र शो पीस की तरह लटककर शोभा बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय 380 बिस्तर वाला अस्पताल है. अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 450 से 500 मरीज ओपीडी में इलाज करने के लिए आते हैं. अस्पताल प्रबंधन आग लगने पर बचाव के लिए सेंट्रलाइज सिस्टम तो लगा रखा है,लेकिन छोटी आग लगने पर तत्काल बुझाने के लिए पूरे अस्पताल में छोटे-छोटे 90 अग्निशमन यंत्र हैं, जिनकी वैधता खत्म हो चुकी है। अग्निशमन यंत्रों की रिफिलिंग का काम पीआर इंटरप्राइजेज रायपुर को मिला है। इस संस्था ने अग्निशमन यंत्र की रिफिलिंग 16 जनवरी 2025 और 29 जनवरी 2025 को थी। जिसकी वैधता तिथि 15 जनवरी 2026 और 28 जनवरी 2026 है। वैधता तिथि समाप्त होने के लगभग एक माह बाद भी इन अग्निशमन यंत्रों की रिफिलिंग नहीं की गई। जो कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही को दर्शा रहा है. वहीं लापरवाही सामने आने के बाद अस्पताल अधीक्षक ने जल्द ही रिफिलिंग की बात कही है।

हमारे अस्पताल में पूरा ऑटोमेटिक फायर प्रूफ सिस्टम लगा हुआ है। छोटी आगजनी की घटनाओं के लिए अग्निशमन यंत्र लगाए गए हैं। आप से मिली जानकारी के मुताबिक उनकी वैधता खत्म हो चुकी है। रिफिलिंग के लिए अस्पताल से ऑर्डर जा चुका है। आपको बता दें कि अगर कहीं आग लग जाती है तो इन्हीं छोटे अग्निशमन यंत्रों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद कहीं सेंट्रलाइज सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है. नियम अनुसार जिम्मेदार संस्था को समय अनुसार रिफिलिंग करना अनिवार्य होता है.लेकिन बड़े सरकारी अस्पताल में ऐसा ना होना कहीं ना कहीं प्रबंधन की उदासीनता को दिखा रहा है

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

रायगढ़ के पारंपरिक बाजारों के कायाकल्प की कवायद शुरू

रायगढ़। जिले के पारंपरिक बाजारों को आधुनिक और सुविधाजनक स्मार्ट बाजार में तब्दील करने की दिशा में एक बड़ी प्रगति हुई है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) की पहल पर जिला प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए जमीनी स्तर पर सुधार कार्य शुरू करने की तैयारी कर ली है। आज इसी सिलसिले में नगर निगम कमिश्नर और कैट की टीम ने संयुक्त रूप से शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों का निरीक्षण किया।ऑनलाइन बाजार की चुनौतियों के बीच स्थानीय व्यापार को संबल पिछले दिनों कैट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं भारत सरकार के व्यापारिक कल्याण बोर्ड के सदस्य अमर पारवानी ने जिलाधीश मयंक चतुर्वेदी से मुलाकात कर शहर के पुराने बाजारों की दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने एक विस्तृत मांग पत्र सौंपते हुए बताया था कि जर्जर सड़कें लटकते बिजली के तार और पार्किंग के अभाव के कारण ग्राहक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की ओर रुख कर रहे हैं। इस स्थिति को बदलने और लोकल फॉर वोकल को चरितार्थ करने के लिए बाजारों का बुनियादी ढांचा सुधारना अनिवार्य है।

छेड़-छाड़ करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, अन्य फरार

रायगढ़। रात्रि चांदमारी रोड पर कार सवार दो युवतियों के साथ छेड़खानी की गंभीर घटना सामने आई है इस मामले को ध्यान में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा-निर्देशन एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा है। घटना में प्रयुक्त ग्रैंड विटारा कार क्रमांक CG13 AW 2410 को भी जप्त किया गया है। मामले में शामिल अन्य चार आरोपी गिरफ्तारी के भय से फरार हैं, जिनकी सघन पतासाजी जारी है। मिली जानकारी के अनुसार 10 फरवरी को महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 09 फरवरी की रात करीब 11 बजे वह अपनी ममेरी बहन के साथ कार से रायगढ़ दवाई लेने जा रही थीं। चांदमारी रोड पर कार रोककर वे आवारा कुत्तों को बिस्किट खिला रही थीं, तभी पीछे से एक नीले कलर की ग्रैंड विटारा कार में सवार पांच युवक पहुंचे और उन पर अशोभनीय टिप्पणियां एवं गंदे इशारे करने लगे। दोनों युवतियां वहां से निकल गईं, जहां युवको ने उनका पिछा तक किया उनकी कार के सामने अपनी कार अड़ा दी।

आंवला प्लांटेशन पर कब्जे का आरोप, बुजुर्ग पहुंचे डीएफओ दरबार

एमसीबी। वनमंडल मनेंद्रगढ़ के परिक्षेत्र अंतर्गत बिहारपुर, सरभोका और नवाडीह प्लांटेशन क्षेत्र में जंगल की अवैध कटाई और कब्जे का मामला सामने आया है। 12 फरवरी को 117 वर्षीय बुजुर्ग संपत यादव शिकायत पत्र लेकर डीएफओ कार्यालय पहुंचे और गंभीर आरोप लगाए। शिकायत पत्र में बताया गया है कि चिरईपानी, नवाडीह और सरभोका प्लांटेशन क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा जंगल साफ कर कृषि कार्य किया जा रहा है। आरोप है कि कुजल सिंह एवं शेर सिंह द्वारा पेड़-पौधों की अवैध कटाई कर शक्तिनदी को बांधकर मठानी कर अवैध रूप से खेत और मेड़ तैयार की जा रही है। इसी प्रकार दिनेश केवट एवं विकास केवट पर भी जंगल उजाड़कर खेती के लिए भूमि तैयार करने का आरोप लगाया गया है। वहीं विमल यादव (पिता स्व. बाबूलाल यादव) द्वारा सरभोका प्लांटेशन क्षेत्र को तार से घेरकर कब्जा करने की शिकायत की गई है। उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा उक्त प्लांटेशन क्षेत्र में आंवला एवं रत्नजोत के पौधे लगाए गए थे।

जाज्वल्यदेव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला 2026 सम्पन्न

जांजगीर-चांपा। जिले के शासकीय हाई स्कूल मैदान, जांजगीर में 11, 12 एवं 13 फरवरी को तीन दिवसीय जाज्वल्यदेव लोक महोत्सव एवं एग्रीटेक कृषि मेला का आयोजन हुआ, जिसका समापन 13 फरवरी को कौशल विकास तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार अनुसूचित जाति विकास मंत्री गुरू खुशवंत सिंह साहेब के मुख्य आतिथ्य में सायं 05 बजे किया गया कार्यक्रम में अति विशिष्ट अतिथि छत्तीसगढ़ विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत एवं जांजगीर-चांपा सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े शामिल हुऐ। कार्यक्रम में विधायक जांजगीर-चांपा ब्यास कश्यप, विधायक अकलतरा राघवेन्द्र कुमार सिंह, विधायक पामगढ़ श्रीमती शेषराज हरवंश, विधायक जैजैपुर बालेश्वर साहू, अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती सत्यलता आनंद मिरी, पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व विधायक एवं अध्यक्ष खनिज विकास निगम सौरभ सिंह, पूर्व संसदीय सचिव अम्बेश जांगड़े, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद जांजगीर-नैला श्रीमती रेखा देवा गढ़ेवाल की उपस्थिति रही।

ऋषभदेव पाण्डेय को पीएचडी की मिली उपाधि

जांजगीर चांपा। कलिंगा विश्वविद्यालय रायपुर द्वारा रसायन शास्त्र में अपना शोध कार्य पूर्ण करने पर युवा प्राध्यापक ऋषभ देव पाण्डेय को पीएचडी (विद्या वाचस्पति) की उपाधि दी गई है। ऋषभ देव ने अपना शोध छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले के भड़ेसर गांव के भूजल में भू-रासायनिक, सूक्ष्मजीवीय और भारी धातुओं के संदूषण का अध्ययन: एक केस स्टडी विषय पर पूर्ण किया है। उन्होंने रसायनशास्त्र विभाग के प्रोफेसर डॉ. अपूर्वा एस के निर्देशन में यह शोध कार्य सम्पन्न किया गया है। उल्लेखनीय है ऋषभदेव विगत 8 वर्षों से कोरबा जशपुर सूरजपुर जिले के विभिन्न शासकीय महाविद्यलयों में अतिथि व्याख्याता के रूप कार्यरत रहने के पश्चात वर्तमान में पामगढ़ स्थित चैतन्य विज्ञान एवं कला महाविद्यालय (स्वशासी) में वे अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

नेशनल हाईवे मुआवजा आर्बिट्रेशन अपील 221 दिन की देरी से दायर

हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित जमीन के मुआवजे से जुड़े मामले में दायर आर्बिट्रेशन अपील को 221 दिन की देरी के कारण खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि केवल धनाभाव और कानूनी जानकारी की कमी जैसे सामान्य कारणों के आधार पर इतनी लंबी देरी को माफ नहीं किया जा सकता। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु की एकलपीठ में हुई। जांजगीर-चांपा जिले के सारागांव निवासी रामकृष्ण, ओंकार, महावीर, परमेश्वरी और रमेश्वरी की जमीन नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित की गई थी। 30 जुलाई 2016 को अवार्ड पारित हुआ। मुआवजे की राशि से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ताओं ने नेशनल

हाईवे एक्ट की धारा 3 प्रतिशत (5) के तहत मामला मध्यस्थ के समक्ष रखा। मध्यस्थ ने 10 नवंबर 2017 को आदेश पारित करते हुए मुआवजे का पुनर्मूल्यांकन केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड, रायपुर के वर्ष 2015-16 के दिशा-निर्देशों के अनुसार करने का निर्देश दिया था। इस आदेश के खिलाफ कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (राष्ट्रीय राजमार्ग) ने धारा 34 के तहत जिला न्यायालय में चुनौती दी। तृतीय जिला न्यायाधीश, जांजगीर ने 2019 में मध्यस्थ का आदेश निरस्त कर दिया। जिला न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपीलकर्ताओं ने धारा 37 के तहत हाईकोर्ट में अपील दायर की, लेकिन यह अपील 221 दिन की देरी से दाखिल हुई। देरी माफी के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत आवेदन पेश किया गया। अपीलकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि धनाभाव, प्रक्रिया की जानकारी का अभाव और व्यक्तिगत परेशानियों के कारण समय-सीमा में अपील दाखिल नहीं हो सकी। उनका कहना था कि देरी जानबूझकर नहीं की गई और यदि देरी माफ कर दी जाए तो प्रतिवादियों को कोई नुकसान नहीं होगा। केंद्र सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने देरी माफी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया। इसमें कहा गया है कि आर्बिट्रेशन मामलों में तय समय-सीमा के बाद देरी को अपवादस्वरूप ही माफ किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि 221 दिन की देरी अत्यधिक है और दिए गए कारण पर्याप्त नहीं हैं। केवल कानूनी जानकारी की कमी या धनाभाव को पर्याप्त कारण नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने यह भी दोहराया कि पर्याप्त कारण सिद्ध होने पर भी देरी माफी अधिकार के रूप में नहीं मिलती, यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। देरी माफी आवेदन खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि जब देरी ही स्वीकार नहीं की जा सकती, तो अपील भी विचारणीय नहीं है। परिणामस्वरूप आर्बिट्रेशन अपील भी खारिज कर दी गई।

जंगल में मिली नवजात शिशु, जांच में जुटी पुलिस

सुकमा। जिले के कोर्रा इलाके के जंगल में नवजात शिशु मिलने की घटना सामने आई है। यह घटना बीती रात करीब 11 बजे के बाद की बताई जा रही है, जबकि शुक्रवार को इस पूरे मामले की जानकारी सुकमा पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।जानकारी के अनुसार, रात के अंधेरे में कुछ ग्रामीण जंगल में गए हुए थे। इसी दौरान उन्हें जंगल में एक सुनसान स्थान से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज की दिशा में जाकर देखने पर वहां एक नवजात शिशु पड़ा मिला। आशंका जताई जा रही है कि कुछ ही समय पहले किसी अज्ञात महिला ने बच्चे को जंगल में छोड़ दिया था।ग्रामीणों ने बिना समय गंवाए मानवता का परिचय देते हुए नवजात को सुरक्षित बाहर निकाला।

देर रात जिला पंचायत उपाध्यक्ष महेश कुंजाम स्वयं नवजात बच्चे को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों द्वारा बच्चे का उपचार किया गया। फिलहाल नवजात की हालत स्थिर बताई जा रही है।बस्तर में इस तरह की घटनाएं बहुत कम सामने आती हैं, लेकिन यह मामला चिंता का विषय बन गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर नवजात को छोड़ने वालों की तलाश शुरू कर दी है और हर पहलू से जांच की जा रही है। ग्रामीणों की सतर्कता, जनप्रतिनिधि की तत्परता और संवेदनशीलता के चलते एक मासूम की जान बच पाई, जिसने एक बार फिर इंसानियत की मिसाल पेश की है।

संक्षिप्त समाचार

सिलयारी अंडरपास गेट से शुरू होगा यातायात 20 फरवरी से

रायपुर। रायपुर रेल मंडल में हावड़ा -मम्बई मुख्य रेल मार्ग स्थित मानव सहित रेलवे समपार फाटक संख्या 403 (कि.मी. 800/21 - 23) (बैकुंठ - सिलयारी के मध्य) के पास रोड अंडर ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है आम जनता के लिए 20 फरवरी से रोड अंडर ब्रिज को खोल दिया जाएगा एवं 403 मानव सहित समपार फाटक को 20 फरवरी से (मध्य रात्रि 24ः00 से) स्थाई रूप से बंद कर दिया जाएगा।

पीएम जनमन आवास योजना से जगदीश बैगा के पक्के घर का सपना हुआ साकार

रायपुर। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत विकासखण्ड गौरेला के ग्राम पंचायत अंधियारखोह के श्री जगदीश बैगा के पक्के घर का सपना साकार हो गया है। उन्हें वर्ष 2023-24 में पक्के आवास की स्वीकृति प्रदान की गई थी। योजना से पूर्व जगदीश बैगा अपने परिवार सहित कच्चे मकान में निवास कर रहे थे। कच्चे मकान में रहने के दौरान उन्हें जंगली कीड़े-मकोड़े, सांप, बिच्छू आदि का खतरा हमेशा सताते रहता था। बरसात के मौसम में छत से पानी टपकने के कारण परिवार को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सीमित आय के कारण पक्के मकान का निर्माण उनके लिए केवल एक सपना मात्र था। शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवास निर्माण से जगदीश बैगा के जीवन में बड़ा बदलाव आया। अब जगदीश अपने परिवार के साथ पक्के आवास में सुरक्षित और सम्मान के साथ निवास कर रहे हैं। पीएम जनमन आवास जगदीश बैगा जैसे जरूरतमंद परिवारों के लिए जीवन स्तर में सुधार का सशक्त माध्यम सिद्ध हो रहा है।

कोंडागांव व फरसगांव में एक दिवसीय अग्नि सुरक्षा कार्यशाला आयोजित

रायपुर। वन विकास निगम, जगदलपुर द्वारा 11 फरवरी को कोंडागांव एवं फरसगांव क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए एक दिवसीय अग्नि सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में क्षेत्रीय कर्मचारियों के साथ-साथ आसपास के ग्रामीणों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यशाला का उद्देश्य वन अग्नि से बचाव, सुरक्षा उपायों की जानकारी तथा आग लगने की स्थिति में त्वरित और सही कार्रवाई के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। अधिकारियों ने बताया कि वन में आग लगने के प्रमुख कारणों में जलती हुई बीड़ी-सिगरेट को लापरवाही से फेंक देना, तेंदूपत्ता संग्रहण के दौरान वृक्षों के नीचे आग लगाकर छोड़ देना तथा अन्य मानवीय असावधानियां शामिल हैं। इन घटनाओं को रोकने के प्रभावी उपायों की भी विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान कंट्रोल्ड बर्निंग (नियंत्रित आग) का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया। साथ ही ब्लोअर मशीन के माध्यम से फायर लाइन कटाई का अभ्यास भी कराया गया, ताकि कर्मचारी आपात स्थिति में प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। अधिकारियों ने कहा कि समय रहते उचित कदम उठाने से बड़ी वन अग्नि घटनाओं को रोका जा सकता है। ग्रामीणों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम गांवों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। वन विकास निगम के अधिकारियों ने भविष्य में भी इस प्रकार के जनजागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम निरंतर आयोजित करने की बात कही।

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग राज्य की बिजली कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं पर करेगा जन-सुनवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राज्य की बिजली कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं पर जन-सुनवाई का कार्यक्रम जारी किया है। आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड तथा छत्तीसगढ़ राज्य भार पोषण केंद्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के ट्रूअप, वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक वार्षिक राजस्व आवश्यकता, टैरिफ निर्धारण तथा पूंजीगत निवेश योजना के अनुमोदन से संबंधित याचिकाओं पर क्षेत्रीय स्तर पर ऑनलाइन जन-सुनवाई आयोजित की जाएगी। आयोग ने बताया कि याचिकाओं का सारांश पूर्व में समाचार पत्रों और आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov. in पर प्रकाशित किया जा चुका है तथा इच्छुक उपभोक्ता और हितधारक निर्धारित तिथियों पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से सुनवाई में भाग ले सकते हैं। निर्धारित कार्यक्रम के तहत 17 फरवरी 2026 को दुर्ग (प्रात: 10:30 से 12 बजे तक), बिलासपुर (दोपहर 12 से 1:30 बजे तक) और राजनांदगांव (दोपहर 3 से 4:30 बजे तक) में जन-सुनवाई होगी। जबकि 18 फरवरी 2026 को अंबिकापुर (प्रात: 10:30 से 12 बजे तक), जगदलपुर (दोपहर 12 से 1:30 बजे तक) और रायगढ़ (दोपहर 3 से 4:30 बजे तक) में जन-सुनवाई आयोजित की जाएगी। आयोग ने उपभोक्ताओं, जन-प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों से जन-सुनवाई में सक्रिय भागीदारी की अपील की है, ताकि टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया में पारदर्शिता और सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल

रेडियो की विश्वसनीयता और एआई की गति मिलकर जनसेवा को बनायेंगे अधिक सशक्त

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम के नए गायन संस्करण का पेन ड्राइव लॉन्च किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने सभी को विश्व रेडियो दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए आकाशवाणी रायपुर और यूनेस्को को इस खास आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी।मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष का विषय 'रेडियो और एआई' अत्यंत सामयिक और उपयोगी है। सूचना क्रांति के इस युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग सभी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में एआई के माध्यम से रेडियो को और अधिक जनोपयोगी बनाने पर गंभीर चिंतन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सही समय पर सही जानकारी नागरिकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसमें रेडियो की भूमिका शुरू से ही अत्यंत प्रभावी रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आकाशवाणी देश का सबसे भरोसेमंद समाचार प्रसारक है। निजी चैनलों के बीच तेज़ी से खबरें देने की प्रतिस्पर्धा के बावजूद आकाशवाणी ने अपनी विश्वसनीय, संतुलित और जनहितकारी सूचना परंपरा को बनाए रखा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में यह सूचना, शिक्षा और स्वस्थ मनोरंजन का सशक्त माध्यम है। उन्होंने रेडियो से जुड़ी अपनी स्मृतियों को साझा करते हुए कहा कि जब दूरस्थ गांवों तक किसी अन्य माध्यम की पहुंच नहीं थी, तब रेडियो ही देश-दुनिया से जुड़ने का एकमात्र माध्यम था। किसानों और ग्रामीण अंचलों के लिए आकाशवाणी आज भी विशेष भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 'मन की बात' जैसे लोकप्रिय कार्यक्रम के लिए रेडियो का चयन इसकी व्यापक पहुंच और प्रभाव को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में आकाशवाणी के छह स्टेशन संचालित हैं तथा रायपुर से विविध भारती सेवा प्रसारित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'रेडियो और एआई' संचार के क्षेत्र में नई क्रांति ला सकता है। एआई की मदद से कंटेंट को अधिक प्रभावी, सटीक और त्वरित बनाया जा सकता है। आपातकालीन सूचनाएं, मौसम पूर्वानुमान, कृषि सलाह और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अधिक तेजी और सटीकता से प्रसारित की जा सकेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ डिजिटल भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। नवा रायपुर में देश का पहला एआई डेटा सेंटर पार्क स्थापित किया जा रहा है, जिससे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और तकनीकी सुरक्षा के क्षेत्र में नए अवसर सृजित होंगे। नई औद्योगिक नीति के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है और डिजिटल तकनीक के जरिए अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी के माध्यम से छत्तीसगढ़ी, गोंडी और हल्बी भाषाओं में प्रसारण से स्थानीय जुड़ाव मजबूत हुआ है और श्रोताओं की रुचि में वृद्धि हुई है।

अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि रेडियो की विश्वसनीयता और एआई की गति मिलकर जनसेवा को और अधिक सशक्त बनाएंगी और विकसित भारत के लिए विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प सभी के सहयोग से अवश्य साकार होगा।

कार्यक्रम में यूनेस्को के रीजनल एडवाइजर ऑफ कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मेशन सुश्री हज़्ज़ाज़ मा%अली ने सभी को विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि रेडियो पूरी दुनिया में सबसे अधिक पहुंच रखता है और सबसे अधिक भरोसे वाला माध्यम है। रेडियो ने कठिन समय में भी अपनी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए दुनिया को सही सूचनाएं प्रदान की। सुश्री अली ने कहा कि एआई के माध्यम से रेडियो को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और इस दिशा में ठोस प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि आकाशवाणी रायपुर छत्तीसगढ़ी और हिंदी भाषा में पूरे प्रदेश विशेषकर आदिवासी बहुल क्षेत्रों तक अपनी सेवाएं दे रहा है। सुश्री अली ने कहा कि यूनेस्को रेडियो के विस्तार के लिए आकाशवाणी के साथ मिलकर नवाचार और तकनीकी पहलुओं पर लगातार सहयोग करेगा।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री शशांक शर्मा, आकाशवाणी के महानिदेशक श्री राजीव कुमार जैन, उप महानिदेशक श्री व्ही. राजेश्वर, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे।

भूपेश को जरुर जाना चाहिए असम क्योंकि भूपेश यानी कांग्रेस के सफाए की गारंटी: ओपी चौधरी

रायपुर। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने शुक्रवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि असम और पश्चिम बंगाल में भाजपा को बंपर जीत हासिल होगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के असम चुनाव प्रचार में जाने के सवाल पर तंज कसते हुए चौधरी ने कहा कि भूपेश बघेल को प्रचार में जरूर जाना चाहिए क्योंकि भूपेश यानी कांग्रेस के सफाए की गारंटी है।

चौधरी आज एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए असम में चुनाव प्रचार जाने के सवाल पर कहा कि पार्टी ने डिप्टी सीएम अरूण साव, केन्द्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उन्हें चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी दी है। वो कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। पार्टी को निश्चित रूप से असम, बंगाल, तमिलनाडु और केरल में बंपर जीत हासिल होगी।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भी असम चुनाव प्रचार के लिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि जहां भी भूपेश बघेल के पांव पड़े हैं, वहां कांग्रेस का सफाया हुआ है। भूपेश पहले उत्तर प्रदेश, असम और बिहार प्रचार के लिए गए थे वहां कांग्रेस का सफाया हो गया। उन्हें वहां प्रचार के जरूर जाना चाहिए, भूपेश बघेल कांग्रेस के सफाए की गारंटी है।

असम और पश्चिम बंगाल विस चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं को दी गई अहम जिम्मेदारियां

इसी साल असम, पश्चिम बंगाल के साथ-साथ केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव होने को है लेकिन इन राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इस पहले सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा ने असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी हैं।

जिसमें उपमुख्यमंत्री अरुण साव, वित्त मंत्री ओपी चौधरी, दुर्ग सांसद विजय बघेल को असम की जिम्मेदारी दी गई है। तीनों नेताओं को 10-10 विधानसभा क्षेत्रों की कमान सौंपी गई है। इसी तरह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए संगठन महामंत्री पवन साय, विधायक राजेश मूणत और शिवरतन शर्मा भी पश्चिम बंगाल में पार्टी के लिए मोर्चा संभालेंगे।

'ग्रहण मंत्री' कहने पर उप मुख्यमंत्री शर्मा ने किया पलटवार

■ कहा- यह शब्दों की निम्नता है, अपने गिरेबान में झांककर देखें लें

रायपुर। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव 'ग्रहण मंत्री' बताए जाने पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे क्या कहा, क्या नहीं कहा, यह तो स्पष्ट हो रहा है। लेकिन ये जो कह रहे हैं, जो भूपेश बघेल कह रहे हैं, उनके शब्दों की निम्नता है। उस पर मैं केवल यही कह सकता हूं कि अपने गिरेबान में झांक कर देख लें।

गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसके साथ ही विधायक देवेंद्र यादव पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस शासनकार के दौरान हुई घटना की याद दिलाते हुए कहा कि टीचर्स डे पर एक टीचर से बलात्कार हुआ था, तब वे कहां थे? पाटन विधानसभा में जब सामूहिक हत्याएं हुई थीं, तब वे कहां थे? उन्हें उस समय भी चिंता करनी चाहिए थी।

गृह मंत्री ने इसके साथ भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के जेल वाले बयान पर कहा कि देखिए फर्क यह है कि आपको कहां-कहां राजनीति करनी है, कहां नहीं करनी है। वही जेल है, वही सेल है। वहां मैं भी था। वही जेल है। मैं बाहर निकाल कर आया तो मैंने नहीं कहा कि वहां ऐसा है, वैसा है। मतलब जबरदस्ती किसी बात पर राजनीति करनी हो तो यह तरीका है कांग्रेस के लोगों का।

दरअसल, पूर्व कांग्रेस नेता, राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल के पॉडकास्ट में भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने कहा था कि उन्हें जेल में कीड़े वाला पानी दिया गया। कैदी इंजेक्शन लगाते थे, और टॉयलेट वाली जगह पर ही रहना पड़ता था।

फर्जी जाति प्रमाण पत्र वालों पर सरकार ने शुरू की कार्रवाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के सहारे सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण का लाभ लेने वालों के खिलाफ प्रशासन ने अपनी नकेल कस दी है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति की बैठक में ऐसे 17 गंभीर मामलों पर सीधी सुनवाई की गई। प्रशासन की इस सख्ती से भविष्य में नियुक्तियों और शैक्षणिक प्रवेश में पारदर्शिता आएगी और दोषियों को जेल के साथ-साथ अपनी नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा।

बैठक के दौरान कुल 17 मामलों की समीक्षा की गई। इनमें से 5 मामलों में प्रमाण पत्र धारकों को अपना पक्ष रखने का अंतिम मौका दिया गया है, जिसके लिए उन्हें अगली बैठक में जरूरी दस्तावेज पेश करने होंगे। वहीं, एक संदेहास्पद मामले में विजिलेंस टीम को दोबारा जमीनी जांच करने के आदेश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि दोष सिद्ध होता है, तो न केवल जाति प्रमाण पत्र रद्द किया जाएगा, बल्कि संबंधित व्यक्ति को नौकरी या शिक्षा में मिले सभी आरक्षण लाभों से तत्काल वंचित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

समिति अब उन सभी 250 मामलों की फाइलें तेजी से निपटा रही है जो लंबे समय से लंबित थे। अगले चरण में उन विभागों को नोटिस जारी किए जाएंगे जहां ये संदिग्ध कर्मचारी वर्तमान में कार्यरत हैं। प्रशासन की इस सक्रियता से फर्जीवाड़ा करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है।

कम लागत में अधिक लाभ की ओर अग्रसर किसान

रायपुर। ब्राम्ही की खेती किसानों के लिए आय का नया और भरोसेमंद फसल है। यह एक प्रमुख औषधीय पौधा है, जिसका उपयोग याददाश्त बढ़ाने, मानसिक शांति और आयुर्वेद में किया जाता है, जिससे इसकी बाजार में मांग बहुत है। छत्तीसगढ़ औषधि पादप बोर्ड जैसे संस्थानों द्वारा इसे प्रोत्साहित किया जा रहा है, और कुछ स्थानों पर सीधे खरीद की सुविधा भी उपलब्ध है, जिससे किसानों को सीधा फायदा हो रहा है।

छत्तीसगढ़ आदिवासी, स्थानीय स्वास्थ्य परंपरा एवं औषधि पादप बोर्ड के प्रयासों से राज्य के किसान अब पारंपरिक धान की खेती के साथ-साथ औषधीय फसलों की ओर भी तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। विशेष रूप से ब्राम्ही की खेती किसानों के लिए आय का नया और भरोसेमंद माध्यम बनकर उभरी है।

बोर्ड द्वारा संचालित औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती योजना के अंतर्गत किसानों को ब्राम्ही की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। ब्राम्ही एक ऐसी औषधीय फसल है, जिसकी लागत कम और लाभ अधिक है। एक बार रोपण करने के बाद 3 से 4 वर्षों तक हर तीन माह में इसकी कटाई की जा सकती है। ब्राम्ही का उपयोग स्मरण शक्ति बढ़ाने, मानसिक स्वास्थ्य सुधारने, मस्तिष्क संबंधी औषधियों तथा सौंदर्य उत्पादों के निर्माण में किया जाता है, जिससे बाजार में इसकी मांग लगातार बनी रहती है।

मैनपाट महोत्सव से सरगुजा की संस्कृति और अस्मिता को मिलेगी व्यापक पहचान: मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री साय ने इस दौरान मैनपाट में पर्यटन के विकास हेतु 1 करोड़ रुपए तथा सीतापुर में सर्व सुविधायुक्त बस स्टैंड के निर्माण हेतु घोषणा भी की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरगुजा जिले में 523 करोड़ 20 लाख 53 हजार रूपए की राशि के 109 विकास कार्यों की सौगात दी। उन्होंने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि सरगुजा की संस्कृति, अस्मिता को दिखाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है यह समारोह। इस महोत्सव से यहां की संस्कृति से देश-दुनिया परिचित होंगे। बाहर से आने वाले एवं स्थानीय कलाकारों को भी मंच मिलेगा और अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।

उन्होंने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मूलमंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। उनके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोग विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का संकल्प लिए हैं। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से ज्यादा माताओं-बहनों के खाते में एक हजार हर महीने आता है, 15 हजार करोड़ से ज्यादा रुपए उनके खाते में जा चुका है। आप लोगों ने देखा है कि 2 साल में यशस्वी प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री के आशीर्वाद के कारण उनके दृढ़ ईच्छा शक्ति के कारण यह क्षेत्र नक्सवाद से मुक्त हो रहा है। मैं अपने प्रदेश के जवानों के साहस को नमन करता हूं।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का तिब्बती बंधुओं द्वारा तिब्बती संस्कृति पर आधारित ताशी शोपा नृत्य के साथ आत्मीय स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री साय ने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टालों का अवलोकन किया तथा शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को हितग्राहीमूलक सामग्रियों का वितरण किया। इस अवसर पर स्थानीय कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं।पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में निरंतर विकास हो रहा है। राज्य सरकार पर्यटन स्थलों के समग्र विकास, आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण और नई संभावनाओं के सृजन की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि मैनपाट जैसे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थल पर पर्यटकों की बढ़ती आवाजाही से स्थानीय युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त हो रहे हैं। विधायक राम कुमार टोप्पो ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन केवल एक उत्सव का शुभारंभ नहीं, बल्कि हमारी समृद्ध संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के प्रति प्रेम का महोत्सव है। मैनपाट महोत्सव जन-गौरव का उत्सव है, जहां प्रकृति ने स्वयं इस धरती को अद्भुत सौंदर्य से सजाया है। विधायक प्रबोध मिंज ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मैनपाट महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर आज क्षेत्र के विकास हेतु 500 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात मिली है। इन कार्यों से मैनपाट में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार होगा तथा पर्यटन गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ में संशोधित गाइडलाइन दरें लागू

रायपुर। छत्तीसगढ़ में 20 नवम्बर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू हैं। राज्य शासन द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को यह निर्देश दिया गया था कि आवश्यकता के अनुसार गाइडलाइन दरों में पुनरीक्षण के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जा सकते हैं।

इसी क्रम में बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर विचार हेतु उप महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में तीनों जिलों से प्राप्त प्रस्तावों का विस्तृत परीक्षण एवं समग्र समीक्षा की गई।विचार-विमर्श उपरांत केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा बिलासपुर, कोरिया एवं सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित नवीन गाइडलाइन दरें इन तीनों जिलों में दिनांक 13 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नवीन गाइडलाइन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अन्य जिलों से प्राप्त होने वाले संशोधित प्रस्तावों पर परीक्षण उपरांत गाइडलाइन दरें चरणबद्ध रूप से जारी की जाएंगी।

कार्यालय, कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्र. 111/नि.शा./ का.अ./ लो.स्वा.यां./खण्ड, रायपुर, दिनांक 06.02.2026

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु मैनुअल निविदा आमंत्रित की जाती है:-

स. क्र.	कार्य का नाम	राशि (रु.लाख में)
1.	रायपुर जिले के विकासखंड तिल्दा के ग्राम भरूवाडीहकला जलप्रदाय योजना के अंतर्गत शिफ्टिंग कार्य हेतु राईजिंग मेन में 90mm dia 10kg/cm2 के UPVC पाईप 300 मीटर, 100 मि.मी. व्यास के जी.आई. पाईप 30 मीटर का प्रदाय कर बिछाने, जोड़ने, परीक्षण कर चालू करने का कार्य।	7.75

उपरोक्त कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति व अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 20.02.2026 सायं 5.30 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड,
रायपुर छत्तीसगढ

जी-252606652/2

अब 'सेवा तीर्थ' होगा प्रधानमंत्री कार्यालय

विवेक शुक्ला

भारत की सत्ता के केंद्र में स्थित साउथ ब्लॉक, केवल एक भवन नहीं, यह स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का साक्षी है। यहीं से दशकों तक ऐसे फैसले लिये गये, जिन्होंने युद्धों की दिशा बदली, अर्थव्यवस्था को नयी राह दी और वैश्विक मंच पर भारत की पहचान गढ़ी। अब 13 फरवरी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यालय 'सेवा तीर्थ' में स्थानांतरित हो गया है। इस बदलाव के साथ एक ऐतिहासिक अध्याय का समापन होगा और सरकारी कामकाज का एक नया दौर आरंभ होगा। प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) 15 अगस्त, 1947 से 12 फरवरी, 2025 तक महान वास्तुकार हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किये गये साउथ ब्लॉक से संचालित होता रहा। साउथ ब्लॉक 1947 में स्वतंत्र भारत की सत्ता का केंद्र बना। इसी भवन के पीएमओ से भारत के सभी प्रधानमंत्रियों ने देश की दिशा तय की। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू (1947-1964) ने यहां से कार्य करना प्रारंभ किया। उनके ही कार्यकाल में भारत की विदेश और रक्षा नीतियों की बुनियाद पड़ी। जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने इसी पीएमओ से देश का नेतृत्व किया। हरित क्रांति की नींव रखने में नॉर्मन बोरलॉग और डॉ एमएस स्वामीनाथन से उनकी महत्वपूर्ण बैठकों का केंद्र भी यही दफ्तर हुआ करता था। वर्ष 1965 के भारत-पाक युद्ध के समय शास्त्री जी ने साउथ ब्लॉक को ही अपना अस्थायी निवास बना लिया था। इंदिरा गांधी (1966-1977, 1980-1984) के कार्यकाल में ही 1971 का ऐतिहासिक भारत-पाकिस्तान युद्ध लड़ा गया। परिणामस्वरूप बांग्लादेश का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ और अन्य शीर्ष सैन्य अधिकारियों की अहम बैठकें यहीं इसी पीएमओ में होती थीं। राजीव गांधी (1984-1989) ने भी यहीं से तकनीकी आधुनिकीकरण की दिशा में कई कदम उठाये। वर्ष 1987 में, श्रीलंका में भारतीय शांति सेना (आइपीकेएफ) भेजने का निर्णय भी यहीं लिया गया। वर्ष 1990 के दशक में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में आर्थिक उदारीकरण की ऐतिहासिक प्रक्रिया भी यहीं शुरू हुई। वित्त मंत्री डॉ मनमोहन सिंह के साथ उनकी महत्वपूर्ण बैठकों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार के लिए खोल दिया। वर्ष 1993 का भारत-चीन सीमा समझौता भी इसी दौर की उपलब्धि रही। अटल बिहारी वाजपेयी (1998-2004) ने प्रधानमंत्री रहते साउथ ब्लॉक से पोखरण परमाणु परीक्षण का निर्णय लिया और कारगिल युद्ध के दौरान रणनीतिक नेतृत्व किया। उसके बाद डॉ मनमोहन सिंह (2004-2014) के कार्यकाल में भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता (2008) हुआ, जिसने भारत को वैश्विक परमाणु व्यवस्था में नयी पहचान दिलायी। मुंबई हमलों (26/11) के बाद आतंकवाद के खिलाफ कड़ी रणनीति भी यहीं बनी। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2014 से अब तक साउथ ब्लॉक से ही कार्य कर रहे थे। उनके नेतृत्व में भारत ने विदेश और रक्षा नीति में अधिक सक्रिय और निर्णायक रुख अपनाया। अब पीएमओ 'सेवा तीर्थ' में स्थानांतरित हो रहा है, जो सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है और जो 2026 तक पूरी तरह विकसित होगा। सेवा तीर्थ-1 में पीएमओ, सेवा तीर्थ-2 में कैबिनेट सचिवालय और सेवा तीर्थ-3 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होगा। 'इंडिया हाउस' नामक आधुनिक कॉन्फ्रेंस हॉल में विदेशी अतिथियों से मुलाकात की जायेगी। अत्याधुनिक सुरक्षा, ओपन वर्कस्पेस और बेहतर समन्वय की सुविधाओं से युक्त यह परिसर रायसीना हिल के निकट स्थित है। प्रधानमंत्री का नया आवास भी पास ही में निर्मित हो रहा है।

तंत्र में लोक को प्रतिष्ठित कीजिए

उमेश चतुर्वेदी

हमने जिस प्रशासनिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया है, उसमें तंत्र की जवाबदेही लोक के प्रति है। हम चाहे जितना भी गर्व करें, लेकिन तंत्र की जवाबदेही के केंद्र में लोक की बजाय अभिजात्य है। यही वजह है कि संकट के क्षणों में हमारे तंत्र को लोक के प्रति जैसी त्वरित भूमिका निभानी चाहिए, वह निभाता नहीं दिखता। लेकिन यदि इसी तंत्र को पता चले कि लोक के बीच कोई अभिजात्य पहचान, महत्वपूर्ण नेता, उद्योगपति, सेलिब्रिटी आदि भी संकटग्रस्त है, हमारे तंत्र की प्रतिक्रिया त्वरित और गहन होती है। तंत्र की सोच की यह खोट ही है कि संकटग्रस्त आम आदमी के लिए त्वरित प्रतिक्रियाएं अपवादस्वरूप ही दिखती हैं। ऑर्ट ऑफ द स्टेट सिटी के रूप में विकसित हो रहे नोएडा में इंजीनियर युवराज के लापरवाही और प्रशासनिक भ्रष्टाचार के मेल से खोदे गए गहरे गड्ढे में डूबने से हुई मौत हो या फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ठीक बीच में जलनिगम के गड्ढे में गिरने से हुई कमल की मौत, भ्रष्टाचार और लापरवाही ही नहीं, तंत्र की सोच को भी जाहिर करती है।

एक मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि नोएडा में गड्ढे में गिरे युवराज की जगह कोई आधुनिक शब्दावली में कहें तो किसी वीआईपी का बेटा होता, सेलिब्रिटी होता या फिर किसी महत्वपूर्ण राजनीतिक हस्ती का पारिवारिक होता तो क्या तंत्र उसी तरह खड़ा रहता, जिस तरह खड़ा रहा और युवराज डूब जाता। कुछ इसी अंदाज में एक बारगी सोचिए कि क्या दिल्ली के बीच में जलनिगम के लिए खोदे गए गड्ढे में गिरे कमल की जगह कोई नेता पुत्र होता, किसी बड़े प्रशासनिक अधिकारी का बेटा होता या फिर किसी बड़े कारोबारी का बच्चा होता तो क्या पुलिस उसी तरह की प्रतिक्रिया करती, जैसा उसने इस मामले में किया। कमल के घर वालों ने देर रात ही पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस का आम दिनों की तरह कहना था कि सुबह आना। दिल्ली पुलिस का ध्येय वाक्य है, सदैव आपके साथ। लेकिन सदैव का उसका साथ सिर्फ वीआईपी के लिए होता है, आम लोगों के लिए नहीं। अगर पुलिस उसी समय सक्रिय हुई होती, उसने सीसीटीवी फुटेज देखे होते तो क्या वह कमल तक नहीं पहुंच जाती?

कमल के गड्ढे में गिरने की जानकारी एक राहगीर ने पास ही स्थित एक कैफे के सुरक्षा गार्ड को दी थी, सुरक्षा गार्ड ने जलबोर्ड कर्मी योगेश को जानकारी दी, योगेश ने ठेकेदार राजेश प्रजापति को फोन कर इसकी जानकारी दी। राजेश घटनास्थल पर आया, लेकिन पुलिस को किसी ने जानकारी नहीं दी। कैफे का गार्ड हो या फिर जलबोर्ड का कर्मी या फिर ठेकेदार, उन्होंने इस घटना को सामान्य तौर पर लिया। संजीदगी किसी ने नहीं दिखाई। सिर्फ इसलिए कि उनके चेतन-अवचेतन में कहीं न कहीं यह बात बैठी हुई है कि गिरने वाला कोई वीआईपी थोड़े ही है कि कुछ होगा। सभी ने सोचा कि देर रात हो गई है, चलो सो जाते हैं। नागरिक हो या कर्मचारी या फिर तंत्र का जिम्मेदार तबका, उनकी ऐसी सोच हमारी सामाजिक और शासन व्यवस्था का कड़वा सच है। सवाल यह है कि क्या हमने लोकतंत्र की जो कल्पना की थी, उसके तहत ऐसी घटनाओं और ऐसी सोच की परिणति की कल्पना की थी?

उदारीकरण के बाद हमने आर्थिक चमक-दमक को बढ़ाने के साथ ही शहरीकरण पर जोर दिया है। शहरीकरण ने आर्थिक लाभ-हानि की बुनियाद पर ही आगे बढ़ने वाली हमारी सोच को विकसित किया है। ग्रामीण सभ्यता वाले अपने देश को हम पूरी तरह शहरीकृत करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। शहर माने सभ्यता का पाठ हमने पढ़ लिया है और उसे ही हकीकत बनाने पर तुले हुए हैं। आधुनिक लोकतंत्र को अगर शहरीकृत लोकतंत्र कहें तो हैरत नहीं होनी चाहिए। शहरीकृत लोकतंत्र की अवधारणा को जाने-अनजाने हमारे मीडिया ने भी बढ़ावा दिया है। व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानने की बजाय हमने उसकी पृष्ठभूमि को अहम मान लिया है। मीडिया भी शहरों में होने वाली दुर्घटनाओं और घटनाओं को जब रिपोर्ट करता है तो वह हैरतअंगेज अंदाज में दिखाने की कोशिश करता है कि शहर में ऐसा हो गया तो बाकी देश का क्या हाल होगा। लोकतंत्र में वोट चाहे शहर के वोटर का हो या गांव के वोटर का, उसकी कीमत एक बराबर है। लेकिन जब यही लोकतांत्रिक व्यवस्था व्यक्तियों के साथ ट्रीटमेंट करने लगती है तो वह इस बराबरी की अवधारणा को भूल जाती है और फिर शहरी नागरिक को ग्रामीण लोक की तुलना में ज्यादा तरजीह देने लगती है। ऐसा करते वक्त उसे भान नहीं रहता कि भारत का समूचा इतिहास, चाहे वह आर्थिक हो, राजनीतिक हो या फिर सांस्कृतिक, ग्रामीण व्यवस्था केंद्रित रहा है। ऐसा नहीं कि गांवों में दुश्मनियां नहीं रहीं, लेकिन गांवों के सोच की बुनियाद आधुनिक शहर केंद्रित सोच की तुलना में हमेशा ज्यादा उदार रही। यह उदारता आधुनिक दौर में भी दिखती है। जब किसी गांव की नहर में कोई कार गिर जाती है तो पूरा गांव उस कार को निकालने दौड़ पड़ता है। जब नदी में कोई महिला आत्महत्या के लिए कूद जाती है तो वहां का लोक उसे बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगा देता है। कभी आग लग जाती है तो लोग वहां फायर ब्रिगेड का इंतजार नहीं करते, अपनी बाल्टी, कटोरे से ही आग बुझाने में जुट जाते हैं। गांधी भारतीय गांवों की इस गहन सोच को समझते थे, इसीलिए उन्होंने अपने संविधान में व्यक्ति की बजाय गांवों को मूल इकाई बनाने का सुझाव दिया था। लेकिन चाहे बाबा साहब अंबेडकर हों या पंडित जवाहर लाल नेहरू, उन्होंने इसे दकियानुसी और पिछड़ी सोच बताते हुए खारिज कर दिया था। संविधान ने भारतीय नागरिक को व्यवस्था की मूल इकाई माना है। लेकिन इस इकाई का महत्व सिर्फ वोट हासिल करने के लिए होता है, जब ट्रीटमेंट का सवाल उठता है तो हमेशा लोक और आम पर वीआईपी, ग्रामीण पर शहरी को तरजीह दी जाती है। इसीलिए संकट के क्षणों में तंत्र की प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं होती। जैसे ही तंत्र को पता चलता है कि संकट में वीआईपी है तो वह बिजली की गति से सक्रिय हो जाता है। सिर्फ राहत के लिए ही नहीं, वीआईपी की सहूलियत के लिए भी, लेकिन संकट ग्रस्त लोक होता है तो उसकी कई बार वह अनदेखी करता है, तो कई बार उस पर मिट्टी भी डाल देता है।

नोएडा की घटना हो या दिल्ली का हादसा, उसने एक बार फिर तंत्र की इसी खामी की ओर इशारा दिलाया है। ऐसे हादसों की जांच होगी, ऐसी घटना ना हो, इसके लिए तंत्र की ओर कदम भी उठाए जाएंगे। दोषी और जवाबदेह लोगों को दंडित करने की बात भी होगी, लेकिन यहां भी पृष्ठभूमि का असर दिखेगा। अधिकारी बच जाएंगे और लीपापोती करने के लिए एकाध निचले तबके के कर्मचारी को दंडित कर दिया जाएगा। फिर इसे भुला दिया जाएगा, फिर तंत्र उसी ढर्रे पर काम करेगा, आने वाले कुछ दिनों में फिर वैसा हादसा होगा और फिर पुराने ढर्रे की तरह तंत्र काम करेगा।

जब तक हम अपने तंत्र की सोच से वीआईपी को इरेज नहीं करेंगे, जब तक हम लोक को सही मायने में प्रतिष्ठित नहीं करेंगे, जब तक नौकरशाही को लोक के प्रति जवाबदेह बनाने की सोच के साथ प्रशिक्षित नहीं करेंगे, तंत्र में बुनियाद बदलाव संभव नहीं। आजादी की अस्सीवीं सालगिरह नजदीक आ रही है। इस मौके पर हमें पीछे मुड़कर देखना होगा और अपने तंत्र की सोच में मौजूद खामियों की ओर ध्यान देना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हम इस तरह सोचने और खामियों को दूर करके तंत्र में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में आगे बढ़ने को तैयार हैं?

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

इसलिए मूल शब्दों पर निष्पक्षता पूर्वक विचार मात्र करने से अनायास ही व्यभिचार विषयक आक्षेप का समूल नाश हो जाता है।

यदि दुर्जनतोष न्याय से शङ्कावादी महाशयों के आग्रहानुसार शिव भगवान् का वेश्या के साथ एक चारपाई पर लेट जाना भी क्षणमात्र के लिये स्वीकार कर लिया जाय तब भी उक्त लीला से शिव भगवान् के पवित्र चरित्र पर कुछ भी दोषारोपण नहीं हो सकता। क्योंकि जो शिव भगवान् विषधर सर्पों को अपने अंगों में निरन्तर लिपटा सकता है तथा प्रलयान्तकारी हलाहल को भी अपने कण्ठ का भूषण बना सकता है, ऐसे निर्विकार एवं सजातीय-विजातीय-भेदशुन्य द्वन्द्वातीत पुरुष से किसी अबला विशेष का श्रानुषंगिक अंग छू जाना भी दोषावह नहीं हो सकता। इस तरह शिवपुराणानुसार शिव भगवान् को ब्रह्म मान लेने पर उक्त आख्यान के किसी भी अंश पर आक्षेप शेष नहीं रहता।

पुरुष दृष्टि से

कदाचित् कोई मूसलचन्द शिव भगवान् के ब्रह्मत्व को भुलाकर वैश्यनाथ अवतारधारी शिव महाराज को भी अपनी तरह भौतिक शरीर धारण करने वाला साधारण पुरुष मान बैठे और पुरुष दृष्टि को सामने रखता हुआ उक्त चरित्र पर आक्षेप करने का साहस करे तो उसे केवल एक बात पर गम्भीरता पूर्वक अवश्य विचार करना चाहिए। कल्पना कीजिये कि शङ्कावादी के कथनानुसार वैश्यनाथ जी महानन्दा के साथ एक पलंग पर न केवल लेटे ही, बल्कि इससे आगे बढ़कर भी जो कुछ शङ्कावादी कह सकता है वह सब कुछ भी हुआ! और यह भी मान ही लीजिए कि इस प्रकार के आचरण से वैश्यनाथ भगवान् अवश्य हो वेश्यागमन के पाप से भी विलिप्त हो गये! परन्तु सोचना तो तह है कि धर्मशास्त्र में उक्त पाप का कुछ प्रायश्चित्त भी लिखा है या नहीं? **क्रमशः...**

वेलेंटाइन डे परंपरा : प्रेम का उत्सव या बाजार का प्रभाव?

कातिलाल मांडोत

प्रतिवर्ष 14 फरवरी को विश्वभर में प्रेम दिवस के रूप में 'वेलेंटाइन डे' मनाया जाता है। भारत में भी पिछले कुछ दशकों से यह दिन विशेष रूप से युवाओं के बीच लोकप्रिय हुआ है। हालांकि समाज का एक वर्ग इसे पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव मानते हुए इसका विरोध करता रहा है, फिर भी यह सच है कि प्रेम जैसी सार्वभौमिक भावना किसी सीमा या संस्कृति की मोहताज नहीं होती। यदि हम इस दिन को केवल पश्चिमी परंपरा के चश्मे से देखने के बजाय व्यापक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से समझें, तो पाएंगे कि प्रेम और वसंत का संबंध हमारी अपनी परंपराओं में भी गहराई से जुड़ा हुआ है।

वेलेंटाइन नामक संत के बारे में मान्यता है कि उन्होंने प्रेम को सामाजिक बंधनों से ऊपर माना और प्रेमी युगलों का विवाह करवाने के कारण उन्हें मृत्युदंड दिया गया। उनकी शहादत प्रेम की पवित्रता और समर्पण का प्रतीक बन गई। भारतीय संदर्भ में देखें तो प्रेम की यह भावना कोई नई नहीं है। भगवान श्रीकृष्ण और राधा का संबंध केवल लौकिक प्रेम का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक माना गया है। कृष्ण का प्रेम मर्यादा और माधुर्य दोनों का अद्भुत संगम है। संस्कृत साहित्य में भी वसंत ऋतु को प्रेम की ऋतु कहा गया है। कालिदास, भास और शूद्रक जैसे साहित्यकारों ने अपने नाटकों और काव्यों में वसंत को मिलन और अनुराग का प्रतीक बताया है। 'मदनोत्सव' और 'वसंतोत्सव' जैसी परंपराएं इस बात की साक्षी हैं कि प्रेम और उल्लास का उत्सव मनाना भारतीय संस्कृति का भी अभिन्न अंग रहा है।

वेलेंटाइन डे के आसपास ही भारत में वसंत ऋतु का आगमन होता है। बसंत पंचमी से लेकर होली तक का समय प्रकृति के नवोन्मेष का काल होता है। सरसों के पीले फूल, कोयल की कूक और मंद समीर वातावरण में एक मधुर भाव जगाते हैं। सूफी संतों ने भी वसंत को प्रेम और भक्ति से जोड़ा। अमीर खुसरो ने अपने गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया के प्रति प्रेम को व्यक्त करने के लिए बसंत और होली के गीतों की रचना की। यह प्रेम सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उत्कर्ष का प्रतीक था। इससे स्पष्ट होता है कि प्रेम का उत्सव मनाने की परंपरा केवल पश्चिम की देन नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक चेतना का भी हिस्सा रही है।

जहां तक 'बेलन टाइम डे' से 'वेलेंटाइन डे' तक की हास्यपूर्ण कथा का प्रश्न है, वह एक व्यंग्यात्मक प्रस्तुति है, जो सामाजिक संबंधों में सम्मान और समानता की आवश्यकता को रेखांकित करती है। इसका ऐतिहासिक आधार चाहे जो भी हो, संदेश यह है कि दांपत्य संबंध प्रेम और आदर पर आधारित होने चाहिए, न कि उत्पीड़न पर। आधुनिक समाज में भी यह संदेश प्रासंगिक है।

आज के समय में युवाओं का वेलेंटाइन डे के प्रति बढ़ता आकर्षण कई कारणों से है। एक ओर वैश्वीकरण और सोशल मीडिया ने सांस्कृतिक सीमाओं को धुंधला कर दिया है, वहीं दूसरी ओर युवा पीढ़ी अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में विश्वास करती है। उनके लिए यह दिन अपने प्रियजनों के प्रति स्नेह प्रकट करने का अवसर है। वे इसे केवल प्रेमी-प्रेमिका के संबंध तक सीमित नहीं रखते, बल्कि मित्रता, पारिवारिक स्नेह और आत्म-प्रेम तक भी विस्तारित कर रहे हैं।

पाकिस्तान के इस्लामी चरित्र की सच्चाई

बलबीर पुंज

6 फरवरी, 2026 को इस्लामाबाद की खादिजा-तुल-कुबरा शिया मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान आत्मघाती विस्फोट हुआ। इसमें 36 लोगों की जान चली गई और 160 से अधिक घायल हो गए। यह केवल एक आतंकी घटना नहीं थी। यह उस गंभीर बीमारी का लक्षण है, जो लंबे समय से पाकिस्तान और मजहब आधारित विचारधारा के भीतर पल रही है, जिसमें गैर-मुस्लिमों के साथ मुसलमान भी मुसलमानों के निशाने पर हैं। यह सिलसिला नया नहीं है। नवम्बर, 2024 में पराचिनार में शिया जुलूस पर हमला हुआ, जिसमें 44 लोग मारे गए। यह जुलूस पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी हजरत फातिमा की याद में निकाला जा रहा था। मार्च, 2022 में पेशावर की कुचा रिसालदार शिया मस्जिद में विस्फोट हुआ, 60 से अधिक लोग मारे गए। 2015 में शिकारपुर की शिया मस्जिद पर हुए हमले में जुमे की नमाज पढ़ रहे 61 लोगों की मौत हुई। 2013 में क्वेटा दो बड़े धमाकों से दहला था, जिसमें 200 से अधिक (अधिकांश शिया) मारे गए थे। ऐसी हृदयविदारक घटनाओं की एक लंबी सूची है।

पाकिस्तान में लगभग 4 करोड़ शिया बसते हैं। पिछले दो दशकों में 4,000 से अधिक शिया मुसलमान इस्लाम के नाम पर जिहादी हमलों में मारे जा चुके हैं। यह दर्दनाक मौतें प्रशासनिक विफलता का परिणाम नहीं, बल्कि उस जहरीली सोच का स्वाभाविक नतीजा है, जिसका आधार ही असहिष्णुता और घृणा हैं। हर बड़ी आतंकी घटना के बाद पाकिस्तान की सत्ता का एक परिचित तरीका सामने आता है-दोष बाहर ढूंढो। इस्लामाबाद की शिया मस्जिद पर हालिया जिहादी हमले के बाद भी बिना ठोस प्रमाण के भारत और अफगानिस्तान पर आरोप मढ़े गए। लेकिन यह समस्या आयातित नहीं है। वास्तव में, यह डंक्षहसा उस वैचारिक अधिष्ठान से प्रेरित है, जिसकी नींव से पाकिस्तान नाम के कृत्रिम

देश का जन्म हुआ और उसी से खुराक लेकर एक राष्ट्र के रूप में जीवित रहने की कोशिश कर रहा है। 'तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान' और 'अहल-ए-सुन्नत-वॉल-जमात' जैसे समूह खुले मंचों से शिया विरोधी भाषण देते रहे हैं। सितम्बर, 2020 में कराची में हजारों सुन्नी कट्टरपंथियों ने रैली निकाली थी, जिसमें शिया मुसलमानों के खिलाफ नारे लगाते हुए उन्हें 'ईशनिंदक' बताकर उनका गला काटने की मांग की गई थी। ऐसे खुलेआम प्रदर्शन इस्लामाबाद सहित पाकिस्तान के अलग-अलग में हिस्सों में हुए थे। पाकिस्तानी सत्ता अधिष्ठान ने वैचारिक बाध्यता के अनुरूप जिहादियों से सीधे संघर्ष की बजाय उनसे बचने या उनका प्रत्यक्ष-परोक्ष सहयोग करने का रास्ता चुना। 2020 में पाकिस्तानी पंजाब में पारित 'तहफ्फुज-ए-बुनियाद-ए-इस्लाम कानून' इसका एक ज्वलंत उदाहरण है, जिसमें इस्लामी मामले में केवल सुन्नी दृष्टिकोण को एकमात्र सच्चा और दूसरे मुस्लिम विचार (शिया सहित) ईशनिंदा के समकक्ष हैं। इस चिंतन का एक वीभत्स रूप 2022 में तब सामने आया, जब डेरा इस्माइल खान में 3 महिला शिक्षकों ने ईशनिंदा के आरोप में अपनी ही एक सहयोगी शिक्षिका की गला रेतकर हत्या सिर्फ इसलिए कर दी, क्योंकि उन्हें एक छात्रा ने बताया था कि उसने सपने में शिक्षिका (मृत) को ईशङ्क्षनदा करते देखा था।आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब उस चिंतन में है, जिसमें आतंकवादियों को 'अच्छे' और 'बुरे' में वर्गीकृत किया जाता है। जब जिहादी भारत या इसराईल को निशाना बनाते हैं, तो वे पाकिस्तान में 'नायक' कहलाते हैं। लेकिन जब वही आतंकी अपनों को ही डंसने लगते हैं, तो पाकिस्तान स्वयं को 'आतंकवाद का पीड़ित' बताने लगता है। क्या यह सच नहीं कि दोनों मामलों में हमलावर एक ही विषाक्त मानसिकता से प्रेरणा पाते हैं?पाकिस्तान का अक्सर तर्क रहा है कि भारत 'मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है।' सच्चाई इस झूठ से कोसों दूर है। 1947 में भारत में लगभग 3 करोड़ मुसलमान थे, आज उनकी संख्या 22-24 करोड़ के बीच है। वे लोकतंत्र में भाग लेते हैं, चुनाव लड़ते हैं और शासन-प्रशासन, सेना, शिक्षा और व्यापार में उनकी मौजूदगी है। बहुसंख्यकों की तरह उन्हें समान और कई मामले में अधिक संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। भारत के खाड़ी देशों (अधिकांश इस्लामी) से मजबूत संबंध हैं। मोदी सरकार में ये रिश्ते और प्रगाढ़ हुए हैं। इसके उलट, पाकिस्तान में गैर-मुस्लिमों की संख्या लगातार घटी है। उनकी महिलाएं मजहबी यातनाओं की शिकार हैं। ड्डक्षहदू, सिख आदि अल्पसंख्यक सार्वजनिक जीवन से लगभग गायब हैं। अहमदिया संवैधानिक रूप से गैर-मुस्लिम घोषित हैं। यह अंतर केवल नीतियों का नहीं, वैचारिक दृष्टिकोण का भी है।

पाकिस्तान में पहचान का संकट भी उसकी समस्या के केंद्र में है। उसका सत्ता-वैचारिक अधिष्ठान अपनी प्राचीन और बहुलतावादी सनातन विरासत से दूरी बनाता है। जब समाज अपनी सांस्कृतिक निरंतरता की बजाय अपनी जड़ों को अस्वीकार करता है, तो वह भ्रम और कुंठा से घिर जाता है। एक ओर पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर गांधार बौद्ध विरासत को अपनी ऐतिहासिक धरोहर मानता है, साथ ही उन इस्लामी आक्रांताओं-गजनवी, गोरी, बाबर, औरंगजेब, अब्दाली, टीपू सुल्तान आदि को भी अपना नायक कहता है, जिन्होंने मजहबी जुनून में इन्हीं सनातन प्रतीकों को रौंदा था। दुनियाभर के मुसलमानों (भारत सहित) के लिए यह एक महत्वपूर्ण संकेत है जिसे अक्सर इस्लामी पहचान का प्रतीक माना जाता है, वह पाकिस्तान अपने जन्म से ही औपनिवेशिक शक्तियों का प्यादा है, जिसका मैं इसी कॉलम में तथ्यों-तर्कों के साथ उल्लेख कर चुका हूं।

क्या मस्जिद में नमाज पढ़ते मुस्लिमों की मजहब के नाम पर सहबंधुओं द्वारा हत्या जायज ठहराई जा सकती है? यह केवल कानून और सुरक्षा का विषय नहीं, बल्कि वैचारिक ड्डक्षचतन का भी प्रश्न है। जब नफरत सामान्य हो जाए, तो हिंसा असामान्य नहीं रह जाती। जम्मू.कश्मीर में कुछ शिया प्रदर्शनकारियों ने यही सवाल उठाया है- 'मस्जिदों में नमाज पढ़ते मुसलमानों को मारना कैसा जिहाद है?' किसी भी राष्ट्र की स्थिरता उसकी विविधता को संभालने की क्षमता पर निर्भर करती है।

आज का इतिहास

1939 जर्मन युद्धपोत बिस्मार्क को शुरू किया गया।
1942 बिलिन नदी की लड़ाई बर्मा में शुरू हुई।
1943 द्वितीय विश्व युद्ध: जनरल हंस-जुर्गन वॉन अर्निम के पांचवें पैंजर सेना ने ट्यूनीशिया में मित्र देशों की स्थिति के खिलाफ एक ठोस हमला किया।
1945 पेरू, पराग्वे, चिली और इक्वाडोर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य बने।
1946 बैंक ऑफ इंग्लैंड का राष्ट्रीयकरण बैंक बना।
1949 पहली बार बुलाई गई इज़राइल की विधायिका केसेट ने उन प्रतिनिधियों की सभा को सफल किया जिन्होंने ब्रिटिश जनादेश युग के दौरान एस्टे यहूदी समुदाय की संसद का कार्य किया था।
1959 क्यूबा पर प्रसिद्ध क्रान्तिकारी फ़ीडल कास्त्रो का शासनकाल आरंभ हुआ।
1961 लॉरेंसियम, धातु रेडियोधर्मी सिंथेटिक तत्व विटहाटोमिक संख्या 103, को पहले लॉरेंस विकिरण प्रयोगशाला में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले के परिसर में बनाया गया था।
1975 मशहूर लेखक सर पेल्हम ग्रेनिवाल वुडहाउस का निधन हुआ।
1985 सीएनएन संवाददाता जेरेमी लेविन को लेबनान में कैद से मुक्त किया गया।
1989 ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम पर आधारित पहला उपग्रह अंतरिक्ष में पृथ्वी की कक्षा के पास स्थापित किया गया।
1989 सलमान रुश्दी को शैतानी छंद के आधार पर फतवा जारी किया गया था, जो एक उपन्यास इस्लामी कट्टरपंथी माना जाता है।
1990 वायेजर 1 अंतरिक्ष जांच ने ग्रहएर्थ की एक प्रतिष्ठित तस्वीर ली जो बाद में पेल ब्लू डॉट के रूप में प्रसिद्ध हुई।
1991 कैरी सी। व्हाइट की मृत्यु के बाद, फ्रांसीसी महिला जीनने कैलमेंट दुनिया की सबसे पुरानी जीवित व्यक्ति बन गईं, और उन्होंने इतिहास में सबसे लंबे समय तक मानव जीवन काल की पुष्टि की, जो 1997 में 122 वर्ष और 164 दिन की उम्र में मर गया।
1992 मार्लेन ओथे ने लगभग 6.96 सेकंड में 60 मीटर इनडोर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड बनाया।
1993 चीन के तांगशान में स्थित लिनक्स डिपार्टमेंटल स्टोर में आग के हमले में 79 लोग मारे गए।
1994 कृतज्ञ काम, जेरी गार्निया ने डेबोराह होन्स को जगाया।
1995 1995 में, कोसेन ने अपने अंगरक्षक को जन्म दिया जिसका नाम बेन थॉमस था।
2005 वीडियो-शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब की शुरूआत हुई।

बांग्लादेश चुनाव : रुको और देखो की रणनीति पर चलेगा भारत

विनोद पाठक

शुक्रवार सुबह जब यह स्पष्ट हो गया कि बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेतृत्व में नई सरकार बनने जा रही है तो क्षेत्रीय कूटनीति की दिशा तुरंत चर्चा का विषय बन गई।

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान को टैग करते हुए उन्हें संसदीय चुनावों में निर्णायक जीत की बधाई दी और यह स्पष्ट किया कि भारत लोकतांत्रिक, प्रगतिशील और समावेशी बांग्लादेश के साथ अपने बहुआयामी संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री के इस संदेश का राजनीतिक महत्व जितना है, उससे कहीं अधिक उसका कूटनीतिक संकेत है। अगस्त 2024 के बाद दोनों देशों के संबंध जिस निचले स्तर तक पहुंच गए थे, उसे देखते हुए यह बधाई संदेश दरअसल संवाद के द्वार फिर से खोलने का एक परिपक्व संकेत माना जा रहा है। यह साफ दिखाता है कि भारत टकराव के बजाय व्यवहारिक और संतुलित कूटनीति के रास्ते पर चलना चाहता है।

हालांकि, भारत और बीएनपी के रिश्तों का इतिहास सहज नहीं रहा है। वर्ष 2001-06 के बीच खालिदा जिया के नेतृत्व वाली बीएनपी सरकार के दौरान दोनों देशों के संबंधों में गहरी कड़वाहट देखी गई थी। उस समय भारत ने बार-बार यह आरोप लगाया था कि बांग्लादेश की धरती का इस्तेमाल पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादी संगठनों, विशेषकर उल्फा, द्वारा किया जा रहा है।

बीएनपी का जमात-ए-इस्लामी जैसे कट्टरपंथी दलों के साथ गठबंधन भारत की चिंता का बड़ा कारण रहा है। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों में कट्टरता, अस्थिरता और सुरक्षा जोखिम बढ़ने की आशंका बनी रहती थी।

बीएनपी लंबे समय से बांग्लादेश फर्स्ट की राजनीति करती रही है। इस नारे को अक्सर भारत-विरोधी रुख के रूप में देखा गया। सीमा विवाद, नदी जल बंटवारा और व्यापार घाटे जैसे मुद्दों पर खालिदा जिया के कार्यकाल में भारत के प्रति कठोर रवैया अपनाया गया था। इसलिए भारत के नीति-निर्माताओं के लिए यह सत्ता परिवर्तन अवसर जितना है, उतनी ही सतर्कता का कारण भी है। वर्ष 2024 के राजनीतिक संकट और उसके बाद के घटनाक्रमों ने बांग्लादेश की राजनीति को बदल दिया है।

अब बीएनपी नेतृत्व को यह अहसास हुआ है कि भारत जैसे बड़े पड़ोसी के साथ स्थायी

टकराव आर्थिक स्थिरता के लिए नुकसानदेह हो सकता है। यही कारण है कि इस बार के चुनाव में तारिक रहमान के नेतृत्व में पार्टी ने अपेक्षाकृत संतुलित और व्यावहारिक रुख अपनाने की कोशिश की है।

नए चुनावी घोषणा-पत्र में भारत के साथ संबंधों को समानता, आपसी सम्मान और गैर-हस्तक्षेप के आधार पर आगे बढ़ाने की बात कही गई है। पार्टी ने यह भी संकेत दिया है कि वह अतीत के सुरक्षा विवादों को पीछे छोड़कर आर्थिक सहयोग और तीस्ता नदी जल बंटवारे जैसे मुद्दों पर तार्किक आधार पर बातचीत करना चाहती है। फिर भी, भारत में शरण लिए बैठीं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग आने वाले समय में एक बड़ी राजनयिक चुनौती बन सकती है।

जहां तक बांग्लादेश के भावी प्रधानमंत्री तारिक रहमान की बात है तो उनकी राजनीतिक छवि भी विरोधाभासों से भरी हुई है। उन्हें एक तरफ अपनी मां की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता है तो दूसरी ओर डिजिटल युग के नेता के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है।

लंदन में लगभग 17 वर्षों के निर्वासन के दौरान उन्होंने तकनीक, सोशल मीडिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पार्टी संगठन को सक्रिय बनाए रखा। इसी कारण उन्हें मिस्टर रिमोट कंट्रोल भी कहा जाता है। कई विश्लेषकों का मानना है कि उनकी मूल विचारधारा

अब भी खालिदा जिया की राजनीतिक सोच से बहुत अलग नहीं है, जिसमें संप्रभुता और मुस्लिम पहचान पर अधिक जोर रहता है। पार्टी के भीतर उनका नियंत्रण भी अत्यंत केंद्रीकृत माना जाता है।

बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा भारत के लिए हमेशा संवेदनशील मुद्दा रही है। वर्ष 2001 के चुनावों के बाद हुई हिंसा और अगस्त 2024 के राजनीतिक संकट के दौरान अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरों ने इस चिंता को और गहरा किया था। हाल के चुनावों में बीएनपी नेतृत्व ने सार्वजनिक रूप से अपने कार्यकर्ताओं को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और खुद को अधिक समावेशी दिखाने की कोशिश की।

इसके बावजूद, जमीन पर अब भी कई हिंदू संगठनों का आरोप है कि स्थानीय स्तर पर डराने-धमकाने और जमीन कब्जाने की घटनाएं जारी रहती हैं। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि नई सरकार के आने से स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी।

भारत के सामने सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौती बांग्लादेश का चीन की ओर संभावित झुकाव है। बीएनपी परंपरागत रूप से चीन के साथ आर्थिक सहयोग को प्राथमिकता देती रही है। बांग्लादेश की ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और आवश्यक वस्तुओं के लिए भारत पर निर्भरता बनी हुई है, लेकिन नई सरकार बांग्लादेश फर्स्ट नीति के तहत चीन से अधिक निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर सकती है।

भारत के लिए यह सुनिश्चित करना चुनौतीपूर्ण होगा कि बांग्लादेश की नई सरकार उसकी सुरक्षा चिंताओं, विशेषकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के प्रति संवेदनशील बनी रहे।

स्पष्ट है कि बीएनपी की जीत के साथ भारत-बांग्लादेश संबंधों में एक नए और चुनौतीपूर्ण अध्याय की शुरुआत हो रही है। पिछले डेढ़ दशक के सहयोगपूर्ण दौर के बाद अब दोनों देशों को अपने रिश्तों को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। गंगा जल समझौते का नवीनीकरण, तीस्ता जल बंटवारा, व्यापारिक साझेदारी और व्यापक आर्थिक समझौते जैसे मुद्दे आने वाले वर्षों में संबंधों की दिशा तय करेंगे। भारत के लिए फिलहाल सबसे उपयुक्त रणनीति रुको और देखो की है। संवाद बनाए रखते हुए अपने सुरक्षा और रणनीतिक हितों की रक्षा करना।

बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन न तो पूरी तरह संकट है और न ही केवल अवसर। यह एक ऐसा मोड़ है, जहां भावनात्मक समीकरणों की जगह व्यावहारिक कूटनीति निर्णायक भूमिका निभाएगी। यदि नई सरकार संतुलित विदेश नीति अपनाती है और भारत अपने नेबरहुड फर्स्ट दृष्टिकोण के साथ लचीलेपन और सतर्कता का संयोजन बनाए रखता है तो यह बदलाव दोनों देशों के संबंधों को नए संतुलन और स्थिरता की दिशा में ले जा सकता है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि यह परिवर्तन दक्षिण एशिया की राजनीति में तनाव बढ़ाएगा या सहयोग का नया अध्याय लिखेगा।

सुप्रीम कोर्ट की सख्ती : राजनीतिक दलों के आत्मविश्वास पर पड़ा एक कड़ा सवाल

कांतिलाल मांडोत

सुप्रीम कोर्ट की दो टूक टिप्पणी कि मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी, केवल एक कानूनी निर्देश भर नहीं है, बल्कि यह देश की राजनीति के मौजूदा मिजाज पर भी एक गहरी टिप्पणी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत का यह रुख राजनीतिक दलों के लिए एक साफ संदेश है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जुड़ी संस्थाओं और कामकाज को लेकर अब अस्पष्टता, दबाव या बयानबाजी के लिए बहुत कम जगह बची है। अदालत ने जिस स्पष्टता के साथ कहा कि अंतिम फैसला केवल निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ही करेंगे और राज्य सरकार की भूमिका सीमित रहेगी, उसने यह भी जता दिया कि चुनावी प्रक्रिया में संस्थागत संतुलन सर्वोपरि है, न कि सत्ता या विपक्ष की राजनीतिक सुविधा। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से राजनीतिक दलों में बेचैनी देखी जा रही थी। एक तरफ इसे मतदाता सूची को शुद्ध और पारदर्शी बनाने की कवायद बताया जा रहा था, तो दूसरी ओर कई दलों को आशंका थी कि इसके जरिए उनके पारंपरिक वोट आधार पर असर पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख के बाद यह आशंका अब और गहरी हो गई है। अदालत ने जब कहा कि असामाजिक तत्वों द्वारा निर्वाचन आयोग के नोटिस जलाने जैसी घटनाएं गंभीर हैं और इस पर राज्य के डीजीपी से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा, तो यह संदेश भी गया कि कानून व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया के बीच किसी तरह की ढील स्वीकार नहीं की जाएगी। यही वह बिंदु है जहां से राजनीतिक दलों की मानसिक स्थिति को समझा जा सकता है।

दरअसल, भारतीय राजनीति में लंबे समय से चुनाव आयोग और अदालतों जैसी संस्थाओं को लेकर एक दोहरा रवैया रहा है। जब कोई फैसला या प्रक्रिया अपने पक्ष में जाती दिखती है, तब वही संस्थाएं लोकतंत्र की रीढ़ बताई जाती हैं, लेकिन जब उनसे असहज सवाल या सख्त निर्देश मिलते हैं, तो उनके इरादों पर संदेह किया जाने लगता है। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद कई दलों में जो खलबली दिखी, वह इसी मानसिकता की उपज है। उन्हें यह डर सता रहा है कि अगर मतदाता सूची की गहन और निष्पक्ष समीक्षा हुई, तो वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। यह डर केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक राजनीति को दर्शाता है जिसमें चुनावी जीत के लिए संस्थागत सुधारों से ज्यादा अहम तात्कालिक लाभ हो गया है। अदालत ने माइक्रो ऑब्जर्वर्स को बदलने, उनके प्रशिक्षण और भूमिका को सीमित करने जैसे निर्देश देकर यह भी स्पष्ट किया कि प्रक्रिया पर किसी एक पक्ष का अनावश्यक प्रभाव नहीं होना चाहिए। यह फैसला प्रशासनिक दृष्टि से भले तकनीकी लगे, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से इसका अर्थ बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि चुनावी प्रक्रिया में शामिल हर कड़ी को जवाबदेह और पारदर्शी होना होगा। यही वह बिंदु है जहां कई राजनीतिक दल असहज महसूस कर रहे हैं। उनके मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वे अपनी राजनीति को केवल भावनात्मक अपील और आरोप-प्रत्यारोप से आगे ले जा पाएंगे, या उन्हें संगठनात्मक और वैचारिक मजबूती पर भी ध्यान देना होगा। राजनीतिक बयानबाजी पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार ने भी इस असहजता को उजागर किया। जब सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत उपस्थिति को लेकर टिप्पणी की गई और सीजेआई ने उसे अनुचित करार दिया, तो यह केवल एक टिप्पणी नहीं थी, बल्कि यह याद दिलाने वाला क्षण था कि संवैधानिक पदों और न्यायिक प्रक्रिया के बीच एक मर्यादा होती है।

जातिगत भेदभाव पर बाजिव है विपक्ष की चिंता?

डॉ हिदायत अहमद खान

भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत उसका संविधान है, जिसने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आदर्शों को राष्ट्र जीवन का आधार बनाया। बावजूद इसके समय-समय पर जाति-संप्रदाय और धर्म के नाम पर भेदभाव किए जाने और हिंसा एवं मावलिंचिंग जैसी कष्टप्रद घटनाएं जब सामने आती हैं तो बेहद अफसोस होता है। ऐसी घटनाएं यह संकेत देती हैं कि संवैधानिक मूल्यों और सामाजिक व्यवहार के बीच अब भी एक गहरी खाई मौजूद है। इस खाई को पाटने की बजाय और चौड़ी करने का कुत्सित कार्य गंदी राजनीति करने वाले तथाकथित नेता करते देखे जाते हैं।

हर चुनाव से पहले इस पर चर्चा होती है और बदस्तूर घटनाएं भी होती हैं, इसलिए सभी कटघरे में खड़े होते हैं, फिर चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। बहरहाल राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा उठाया गया जातिगत भेदभाव का मुद्दा इसी खाई की ओर ध्यान आकर्षित करता है। इस संदर्भ में विपक्ष की चिंता न केवल उचित है, बल्कि लोकतांत्रिक विमर्श का आवश्यक हिस्सा भी है। ओडिशा के एक आंगनवाड़ी केंद्र में दलित महिला द्वारा भोजन बनाए जाने के कारण बच्चों के बहिष्कार की घटना केवल एक स्थानीय विवाद नहीं मानी जा सकती। यह उस मानसिकता का प्रतीक है, जो आधुनिक भारत के विकास और प्रगति के दावों को चुनौती देती है।

आंगनवाड़ी केंद्र देश के सबसे संवेदनशील सामाजिक संस्थानों में से हैं, जहां बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य और प्रारंभिक शिक्षा की नींव रखी जाती है। यदि वहीं जातिगत पूर्वाग्रह के आधार पर बहिष्कार जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो यह न केवल एक कर्मचारी का अपमान है, बल्कि उन बच्चों के अधिकारों का भी हनन है, जिन्हें समान अवसर और पोषण मिलना चाहिए। यहां यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान का अनुच्छेद 14 सभी को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 15 धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है, जबकि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन की स्पष्ट घोषणा करता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 21(क) शिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है और अनुच्छेद 47 राज्य को पोषण स्तर और जनस्वास्थ्य सुधारने की जिम्मेदारी

सौंपता है। यदि जातिगत सोच के कारण पोषण कार्यक्रमों का बहिष्कार होता है, तो यह इन संवैधानिक प्रावधानों की भावना के विपरीत है। अतः ऐसे तमाम मामलों और घटित हुई घटनाओं की जितनी निंदा की जाए कम होगी।

राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने इस संबंध में जिन अन्य घटनाओं का उल्लेख किया उनमें मध्य प्रदेश में आदिवासी मजदूर के साथ अमानवीय व्यवहार, गुजरात में दलित कर्मचारी की आत्महत्या और चंडीगढ़ में संस्थागत भेदभाव जैसी घटनाएं भी शामिल हैं। ये मामले दर्शाते हैं कि समस्या केवल सामाजिक स्तर तक सीमित नहीं है। यदि संस्थागत ढांचे में भी पूर्वाग्रह मौजूद हैं, तो यह स्थिति और अधिक गंभीर हो जाती है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम जैसे कठोर कानूनों का अस्तित्व तभी सार्थक है, जब उनका प्रभावी और निष्पक्ष क्रियान्वयन हो। यह भी सच है कि जातिगत भेदभाव का मुद्दा अक्सर राजनीतिक बहस का हिस्सा बन जाता है।

सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप होते हैं, जिससे मूल समस्या कभी-कभी राजनीतिक शोर में दब जाती है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मुद्दे की गंभीरता कम हो जाती है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका केवल आलोचना करना नहीं, बल्कि सरकार और समाज को आईना दिखाना भी है। यदि विपक्ष सामाजिक न्याय के प्रश्न को उठाता है, तो उसे केवल राजनीतिक चश्मे से देखने के बजाय व्यापक सामाजिक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह ऐसी घटनाओं को अलग-थलग घटनाएं कहकर टालने के बजाय उनकी जड़ तक पहुंचे।

त्वरित और निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई और पीड़ितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। साथ ही, सामाजिक जागरूकता अभियान चलाकर यह संदेश देना भी उतना ही जरूरी है कि जातिगत भेदभाव न केवल अवैध है, बल्कि नैतिक रूप से भी अस्वीकार्य है। विशेष रूप से आंगनवाड़ी, विद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में समानता और सम्मान के मूल्यों को व्यवहार में उतारने की जरूरत है। सामाजिक न्याय केवल विधायी प्रावधानों से स्थापित नहीं होता; वह समाज की मानसिकता में परिवर्तन से आता है। जब तक समाज के हर वर्ग में यह भावना विकसित नहीं होगी कि सम्मान और अधिकार जन्म से नहीं, बल्कि अच्छे मानव होने के नाते मिलते हैं, तब तक कठोर कानूनों की आवश्यकता बनी रहेगी।

बच्चों के सामने यदि समानता का व्यवहार प्रस्तुत किया जाएगा, तभी वे भविष्य में भेदभाव से मुक्त समाज का निर्माण कर सकेंगे। ऐसे में जातिगत ही नहीं बल्कि किसी भी प्रकार का भेदभाव जो समाज और समुदाय को तोड़ने का काम करता है वाला प्रश्न किसी एक दल या विचारधारा का नहीं, बल्कि भारतीय समाज की आत्मा का प्रश्न है। विपक्ष की चिंता इसलिए वाजिब है क्योंकि वह संविधान में निहित उस मूल भावना की याद दिलाती है, जिसे हम अक्सर भाषणों में दोहराते हैं पर व्यवहार में भूल जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि सामाजिक न्याय को राजनीतिक नारे से आगे बढ़ाकर राष्ट्रीय संकल्प बनाया जाए। तभी हम सही मायने में उस भारत की ओर बढ़ सकेंगे, जिसका सपना आजादी के दीवानों और संविधान निर्माताओं ने देखा था।

लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास!

डॉ श्रीगोपाल नारसन

विपक्ष के 128 लोकसभा सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने के लिए एक नोटिस लोकसभा महासचिव को सौंप दिया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बताया कि उन्होंने नियम 94सी के तहत लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बोलने की इजाजत नहीं देने, साथ ही कांग्रेस की महिला सांसदों पर सदन में अनुचित स्थिति पैदा करने के आरोपों पर विपक्ष अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए यह प्रस्ताव लाया है।लोकसभा में कांग्रेस के उप नेता गौरव गोगोई, कांग्रेस के मुख्य सचेतक कोडिकुनिल सुरेश और सांसद मोहम्मद जावेद तथा अन्य कई सांसद नोटिस सौंपने वालो में शामिल है।लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के मानदंडों के नियम 198 के अनुसार, विपक्ष को लोकसभा में मतदान से पहले अविश्वास प्रस्ताव के अपने अनुरोध के लिए औचित्य प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है।अविश्वास प्रस्ताव की पूरी प्रक्रिया लोकसभा की प्रक्रिया व कार्य संचालन प्रणाली के नियम 198 (1) से नियम 198 (5) तक के तहत पूरी की जाती है।इस प्रक्रिया के तहत नियम 198 (1) (क) के तहत अविश्वास प्रस्ताव पेश करने वाले सांसद को पहले स्पीकर के जरिये सदन की अनुमति लेनी पड़ती है।सदन की अनुमति के लिए नियम 198 (1) (ख) के मुताबिक, प्रस्ताव की जानकारी सुबह 10 बजे से पहले लोकसभा के महासचिव को देनी पड़ती है।नियम 198 (2) के तहत प्रस्ताव के साथ सांसद को 50 सांसदों के समर्थन वाले हस्ताक्षर दिखाने होते हैं।नियम 198 (3) के तहत लोकसभा अध्यक्ष से प्रस्ताव को अनुमति मिलने के बाद उस पर चर्चा का दिन तय होता है। चर्चा प्रस्ताव पेश होने के 10 दिन के अंदर करानी होती है।नियम 198 (4) के तहत अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के अंतिम दिन लोकसभाध्यक्ष वोटिंग कराते हैं और उस आधार पर फैसला होता है।नियम 198(5) के तहत लोकसभा

अध्यक्ष को टिप्पणी के लिए समय सीमा निर्धारित करने का अधिकार है। यदि प्रस्ताव सदन द्वारा अनुमोदित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है ।अब तक लोक सभा में 27 बार अविश्वास प्रस्ताव रखे जा चुके हैं।लोक सभा में सबसे पहला अविश्वास प्रस्ताव अगस्त 1963 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ जे बी कृपलानी ने पेश किया था। लेकिन विपक्ष सरकार गिराने में नाकाम हो गया था, क्योंकि इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े और विरोध में 347 वोट पड़े थे।लेकिन सन 1978 में लाये गए अविश्वास प्रस्ताव ने मोरारजी देसाई सरकार को गिरा दिया था।अब तक सबसे ज्यादा 4 बार अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का रिकॉर्ड माकपा सांसद ज्योतिर्मय बसु के नाम है। उन्होंने अपने चारों प्रस्ताव इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ रखे थे।सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाली भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार रही है। इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ 15 अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गये थे।इसके अलावा पी? वी? नरसिम्हा राव और लाल बहादुर शास्त्री की सरकारों ने तीन-तीन बार अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था।पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार इंदिरा गाँधी सरकार और दूसरी बार पी? वी? नरसिम्हा राव सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था ।संयोग की बात है कि अटल सरकार के खिलाफ भी दो बार सन1996 व सन1998 अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था और वे दोनों बार हार गये थे। सन 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था,लेकिन यह प्रस्ताव गिर गया था।

लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला पर आरोप हैं कि वो विपक्ष के साथ भेदभाव करते हैं और सांसदों को बोलने का मौका कम देते हैं।हालांकि ये पहली बार नहीं है, जब किसी लोकसभाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा हो। संसद के इतिहास में कई बार ऐसा हो चुका है।

अविश्वास प्रस्ताव भारतीय संसदीय परंपरा का ही एक हिस्सा है। जब भी विपक्ष को सरकार या फिर लोकसभाध्यक्ष पर भरोसा नहीं होता है तो उन्हें हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। लोकसभाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 94(सी) के तहत लाया जाता है, इसे मोशन ऑफ रिमूवल कहा जाता है।इसके तहत लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। वोटिंग में बहुमत मिलने पर अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।भारतीय संसद के इतिहास में पहली बार सन1954 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लोकसभा के पहले अध्यक्ष मावलंकर के खिलाफ ये प्रस्ताव लाया गया था। सोशलिस्ट पार्टी के नेता विग्नेश्वर मिसिर ये प्रस्ताव लाए थे।इस प्रस्ताव पर करीब दो घंटे तक चर्चा हुई थी, हालांकि बाद में उसे खारिज कर दिया गया। इस प्रस्ताव को जवाहर लाल नेहरू ने सदन की गरिमा का सवाल बताया था।सन1954 के बाद लोकसभाध्यक्ष के खिलाफ दूसरा प्रस्ताव सन 1966 में लाया गया।लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुकम सिंह के खिलाफ ये प्रस्ताव था।वहीं तीसरी बार सन1987 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ये प्रस्ताव तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ के खिलाफ लाया गया था।पिछले तमाम प्रस्तावों की तरह ये अविश्वास प्रस्ताव भी खारिज हो गया था।अब देखना यह है कि यह अविश्वास प्रस्ताव कितना चल पाता है।इससे लोकसभाध्यक्ष की कुर्सी जाती है या फिर यह प्रस्ताव धड़ाम गिरता है।फिलहाल तो संख्या बल देखते हुए ऐसा नही लगता कि ओम बिरला की कुर्सी जाएगी,बाकी आने वाला वक्त बताएगा।

मध्यप्रदेश में इस माह अंत तक हो सकता है मंत्रिमंडल में फेरबदल

सुरेश तिवारी

डॉ. मोहन यादव ने दिसंबर में मुख्यमंत्री पद पर दो साल पूरे कर लिए। तब से ही उनके मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चलती रही हैं। अब खबर आ रही है कि विधानसभा के बजट सत्र के बाद इस माह के अंत तक मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। मुख्यमंत्री पिछले सप्ताह दो दिन लगातार दिल्ली में रहे। प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी उनके साथ थे। दोनों नेताओं ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की। दोनों नेताओं की दिल्ली यात्रा को मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडलों में नियुक्तियों से जोड़ा जा रहा है। पता चला है कि इस बार परफॉर्मेंस के आधार पर मंत्रियों की छुट्टी होगी। इससे संबंधित एक रिपोर्ट कार्ड भी मुख्यमंत्री के पास है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के पुनर्गठन में 6 मंत्रियों की छुट्टी की जा सकती है। इन मंत्रियों को पार्टी संगठन में कहीं समायोजित करने की बात भी चर्चा में है। उज्जैन के एक और पूर्व कलेक्टर अजातशत्रु श्रीवास्तव भी मुख्यमंत्री के पावर कॉरिडोर में शामिल हो गए हैं। अजातशत्रु को अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन संस्थान का सलाहकार नियुक्त किया गया है। इस संस्थान के अध्यक्ष मुख्यमंत्री हैं। जाहिर है वे अब मुख्यमंत्री के सलाहकार की भूमिका में रहेंगे। वर्तमान में उज्जैन के पूर्व कलेक्टरों में अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई मुख्यमंत्री के एसीएस के साथ ही ऊर्जा विभाग के भी एसीएस हैं। एसीएस शिव शेखर शुक्ला अपर मुख्य सचिव गृह हैं। उज्जैन के पूर्व कलेक्टर रहे आशीष सिंह वर्तमान में वहां के कमिश्नर और सिंहस्थ मेला अधिकारी हैं। उज्जैन के एक और पूर्व कलेक्टर मनीष सिंह के पास राज्य के परिवहन विभाग का दायित्व है। एक और पूर्व उज्जैन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम मंडी बोर्ड के एमडी के साथ ही राज्य कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के भी एमडी हैं।

भोपाल के पुलिस आयुक्त संजय कुमार ने ईरानी डेरे पर बड़ा ऑपरेशन करते हुए 408 आरोपियों पर शिकंजा कसा है। इस ऑपरेशन के दौरान सैकड़ों वारंटी और फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा सोना, गांजा और नकदी भी जब्त की गई। दरअसल, भोपाल में ईरानी समुदाय के अपराधों को लेकर पिछले कई महीने से लोग परेशान थे। नवागत पुलिस आयुक्त ने इस काम को हाथ में लेकर एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। इसे पुलिस आयुक्त की धमाकेदार एंट्री माना जा रहा है। बता दें, संजय कुमार इसके पहले बालाघाट के आईजी के पद पर पदस्थ रहे हैं। वहां, उन्होंने नक्सलियों का सफाया करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। माना जा रहा है कि उनके अच्छे काम के लिए उन्हें पुलिस कमिश्नर भोपाल के पद से नवाजा गया। प्रदेश में भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा द्वारा नवग्रह मंदिर की स्थापना कराई जा रही है। डबरा में उन्होंने भव्य मंदिर बनवाया है। दावा किया जा रहा है कि यह विश्व का इकलौता मंदिर है, जिसमें सभी नव गृह अपनी-अपनी अर्धांगिनी के साथ अलग-अलग मंदिरों में विराजमान किए गए हैं। हाल ही में जब नरोत्तम मिश्रा नवग्रह मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करा रहे थे, तब कलश यात्रा के दौरान भगदड़ मच गई। नरोत्तम मिश्रा ने जैसे तैसे मामले को संभाला। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि 20 फरवरी के बाद क्या नरोत्तम मिश्रा की राजनीतिक गृह दशा बदलेगी?

इन 6 लोगों को नहीं खाना चाहिए मखाना, सेहत को फायदे नहीं मिलेंगे सिर्फ नुकसान

मखाना, जिसे हम अक्सर चाय के साथ या हलके स्नैक्स के तौर पर खाते हैं, सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। इसमें ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, फाइबर, और एंटीऑक्सीडेंट्स, जो हमारे शरीर को मजबूती देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मखाना सभी के लिए सही नहीं होता? कुछ लोगों के लिए यह हानिकारक भी हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी से जुड़ी समस्याओं से परेशान हैं, तो मखाना खाने से पहले एक बार सोच लीजिए। आइए जानते हैं किन 5 लोगों को मखाना खाने से परहेज करना चाहिए।

डायबिटीज के रोगी

मखाना में उच्च मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जो ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, तो उसे मखाना का सेवन सीमित मात्रा में और डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। इसके अलावा, मखाना का सेवन ज्यादा करने से शरीर में ग्लूकोज का स्तर असंतुलित हो सकता है, जिससे डायबिटीज की स्थिति खराब हो सकती है।

गैस्ट्राइटिस और पाचन समस्याओं वाले लोग

मखाना के सेवन से कुछ लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इसमें फाइबर की अधिक मात्रा होती है, जो कभी-कभी पेट में गैस, सूजन, और कब्ज जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति को गैस्ट्राइटिस, पेट की जलन, या अन्य पाचन समस्याएं हैं, तो उसे मखाना खाने से बचना चाहिए या फिर इसे सीमित मात्रा में खानी चाहिए।

किडनी रोगी

मखाना में पोटेशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो किडनी के रोगियों के लिए हानिकारक हो सकता है। किडनी की बीमारी होने पर, शरीर से पोटेशियम की सही मात्रा बाहर नहीं निकल पाती, जिससे पोटेशियम का स्तर बढ़ सकता है और यह हृदय की समस्याएं पैदा कर सकता है। इसलिए, किडनी रोगी को मखाना खाने से बचना चाहिए या फिर इसे बहुत कम मात्रा में लेना चाहिए।

एलर्जी से प्रभावित लोग

कुछ लोगों को मखाना से एलर्जी हो सकती है, जिससे उन्हें त्वचा पर दाने, खुजली, या अन्य एलर्जी के लक्षण हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को मखाना खाने के बाद कोई एलर्जी के लक्षण दिखते हैं, तो उसे मखाना से बचना चाहिए। ऐसे लोग मखाना के सेवन से पहले डॉक्टर से परामर्श लें।

हाई ब्लड प्रेशर

हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत से दो चार हो रहे लोगों को मखाना ना खाने के लिए कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मखाना में सोडियम होता है और इससे हाई ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। इसीलिए हाई ब्लड प्रेशर से परेशान लोगों को मखाना ना खाने या कम खाने की कोशिश करनी चाहिए।

गर्भवती महिलाएं

गर्भवती महिलाओं को मखाना का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। मखाना में कुछ प्रकार के तत्व होते हैं जो शरीर में गर्मी पैदा कर सकते हैं, और ज्यादा सेवन से यह गर्भावस्था में असहज महसूस करवा सकता है। गर्भवती महिलाएं पहले डॉक्टर से सलाह लें कि मखाना उनका सेवन कर सकती हैं या नहीं, और यदि कर सकती हैं, तो कितनी मात्रा में करें।

मखाना खाने के फायदे : हालांकि, मखाना का सेवन बहुत से लोगों के लिए फायदेमंद होता है। इसमें उच्च मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, और मिनरल्स होते हैं, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यह हृदय स्वास्थ्य, पाचन, वजन घटाने, और त्वचा की सेहत के लिए भी लाभकारी है।

सुबह उठते ही पिएं लौंग का पानी, ब्लड शुगर से लेकर बॉडी डिटॉक्स तक मिलेंगे ये बेहतरीन फायदे

एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज और जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर लौंग का पानी आपके स्वास्थ्य, त्वचा और बालों के ग्रोथ के लिए बेहद फायदेमंद है. यह नेचुरल तरीके से आपको इस तरह के लाभ पहुंचाता है. आहार विशेषज्ञ और वेट मैनेजमेंट विशेषज्ञ डॉ. प्रत्यक्ष भारद्वाज इसे फएंटीऑक्सीडेंट का एक पावरहाउसफ कहते हैं जो पाचन, प्रतिरक्षा और यहां तक ??कि वेट मैनेजमेंट में भी मदद करता है.

स्वास्थ्य लाभ

पाचन को बढ़ावा देता है और सूजन से लड़ता है : लौंग का पानी आपके पाचन तंत्र के लिए अद्भुत काम करता है।यह सूजन, गैस्ट्रिक समस्याओं और अपच को कम करने में मदद करता है. डॉ. भारद्वाज कहते हैं, फलौंग का पानी सूजन और गैस्ट्रिक समस्याओं के लिए एक प्राकृतिक उपाय है. यह डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया का भी समर्थन करता है.

वजन घटाने में मदद करता है : लौंग का पानी आपके मेटाबॉलिज्म को बहुत जरूरी बढ़ावा दे सकता है. इसका एक्टिव कंपाउंड , यूजेनॉल, फ़ैट मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने में मदद करता है, जिससे यह वेट मैनेजमें डेली रूटीन में सहायक होता है. ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है : यदि आप अपने ब्लड शुगर को नेचुरल तरीके से मैनेज करना चाहते हैं, तो लौंग का पानी आजमा कर देश सकते है. लौंग में मौजूद यूजेनॉल ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है और ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ का समर्थन करता है.

रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करता है : लौंग के पानी में एंटीऑक्सीडेंट की हाई अमाउंट होने के कारण यह आपके रोग प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाता है, जिससे आप आम संक्रमणों और बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं.

आपके दांतों के लिए अच्छा : लौंग के पानी के एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी मुंह में सूजन को कम करके मौखिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं. लौंग के पानी से कुल्ला करने से आपकी सांसों को भी तरोताजा करने में मदद मिल सकती है.

सौंदर्य लाभ

मुंहासे और दाग-धब्बों से लड़ता है : लौंग के पानी के सूजनरोधी और रोगाणुरोधी गुण मुंहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने, लालिमा को कम करने और साफ त्वचा को बढ़ावा देने में मदद करते हैं.

आपकी त्वचा को चमकदार बनाता है : लौंग के पानी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट मुक्त कणों से लड़ते हैं, जो सुस्ती और समय से पहले बुढ़ापे का कारण बन सकते हैं. नियमित उपयोग से आपकी त्वचा चमकदार और स्वस्थ दिख सकती है.

चिड़चिड़ी त्वचा को आराम देता है : अगर आपकी त्वचा में खुजली या जलन है, तो लौंग के पानी के शांत करने वाले गुण राहत दे सकते हैं.

बालों के लिए लाभकारी

बालों के रोम को मज़बूत बनाता है : लौंग का पानी स्कैल्प को पोषण देता है और बालों के रोम को मजबूत बनाता है, जिससे बालों का झड़ना कम होता है और विकास को बढ़ावा मिलता है.

रूसी से लड़ता है : लौंग के पानी के रोगाणुरोधी गुण रूसी और खुजली को कम करने में मदद करते हैं, जिससे आपकी स्कैल्प स्वस्थ रहती है.

बालों में चमक लाता है : लौंग के पानी से अपने बालों को धोने से उनमें प्राकृतिक चमक और कोमलता आ सकती है, जिससे आपके बाल ज्यादा जीवंत दिखते और महसूस होते हैं.

सावधानी बेहद जरूरी

माना कि लौंग के पानी के कई लाभ हैं, लेकिन नियंत्रित मात्रा में इसका सेवन करना बेहद जरूरी है, इसके अधिक इस्तेमाल से जलन या संवेदनशीलता हो सकती है. डॉ. भारद्वाज सलाह देते हैं कि अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप पेशेवर मार्गदर्शन के साथ लौंग के पानी को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

लौंग का पानी कैसे बनाएं

लौंग का पानी बनाना आसान और किफायती है. जानें बनाने की विधि

सामग्री

1 चम्मच साबुत लौंग

1 कप पानी

बनाने की विधि

सबसे पहले एक कप पानी उबालें और इसमें लौंग डालें और उन्हें 10-15 मिनट तक भीगने दें. लौंग निकालने के लिए पानी को छान लें। पीने या अपनी त्वचा या बालों पर इस्तेमाल करने से पहले इसे आरामदायक तापमान पर ठंडा होने दें. अतिरिक्त स्वाद और लाभों के लिए, आप इसमें नींबू का एक टुकड़ा या एक चम्मच शहद मिला सकते हैं. सुबह खाली पेट एक कप लौंग का पानी रोजाना पिने से बहुत लाभ मिलता है.

डायबिटीज के मरीज

भूलकर भी न करें इन फलों का सेवन, बढ़ सकता है ब्लड शुगर का लेवल

डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है. आज के समय में इस बीमारी से करोड़ों लोग पीड़ित है. इस रोग से पीड़ितों को अपने खानपान का खास ख्याल रखना पड़ता है. इसके साथ ही जीवनशैली में भी बदलाव की जरूरत होती है. यह एक ऐसी बीमारी जिसमें डायबिटीज से पीड़ितों का ब्लड शुगर लेवल काफी बढ़ जाता हैं, जिसके चलते उन्हें कई तरह की स्वास्थ्य समस्या हो सकती है. यहां तक की हाई ब्लड शुगर के चलते कभी-कभी पीड़ितों की जान भी जा सकती है. इसलिए इसको कंट्रोल में रखना बेहद जरूरी होता है. आज हम इस खबर में बताने जा रहे हैं कि डायबिटीज मरीजों को डॉक्टरों के द्वारा चीकू फल खाने से बचने को क्यों कहा जाता है...

डायबिटीज में भूलकर भी ना खाएं चीकू

हम सबको पता है कि चीकू एक ऐसा फल है, जो न सिर्फ खाने में स्वादिष्ट है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी होता है. खास बात यह है कि इस फल के अलावा बीज और पत्तियां भी काफी गुणकारी हैं. फिर भी डॉक्टरों के मुताबिक, डायबिटीज पेशेंट को चीकू फल खाने से बचना चाहिए, ऐसा इसलिए क्योंकि चीकू में कार्बोहाइड्रेट बहुत हाई अमाउंट में होता है और इस फल में शुगर की मात्रा भी ज्यादा होती है. बता दें, चीकू में मौजूद ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट नेचुरल शुगर के रूप में होता है. इसलिए डॉक्टरों के द्वारा हाई ब्लड शुगर से पीड़ित लोगों को चीकू फल नहीं खाने की सलाह दी जाती है. इसके साथ ही डायबिटीज के मरीजों को इन फलों से भी बचना चाहिए. इसमें अनानास, लीची, केला, आम, तरबूज शामिल है.

प्री-डायबिटीज में भूलकर भी ना खाएं चीकू

प्री-डायबिटीज पेशेंट को भी म चीकू नहीं खाने की सलाह दी जाती है. बता दें, चीकू में शुगर की मात्रा अधिक होती है, जिससे मरीज का ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है. चीकू में कैलोरीज भी अधिक होती हैं. बता दें, चीकू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अधिक होने की वजह से इसका सेवन करने से ब्लड शुगर लेवल तुरंत बढ़ने लगता है

ध्यान देनें वाली बात

यदि आपको हाई ब्लड शुगर (हाइपरग्लाइसेमिया) है तो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 130 एमजी/डीएल से ऊपर रहेगा और रैंडम ब्लड शुगर 180 एमजी/डीएल से अधिक रहेगा. यदि आपका ब्लड शुगर लेवल लगातार इन सीमाओं से ऊपर है, तो आपको प्री-डायबिटीज या डायबिटीज हो सकता है. अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया, तो यह हार्ट डिजीज, तंत्रिका समस्याओं और किडनी की बीमारियों जैसी गंभीर चिकित्सा समस्याओं का कारण बन सकता है.

अगर आपको लो ब्लड शुगर (हाइपोग्लाइसीमिया) की समस्या है, तो आपका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 70 एमजी/डीएल से कम रहेगा और रैंडम ब्लड शुगर 60 एमजी/डीएल से कम रहेगा. आपकों लो ब्लड शुगर के कारण चक्कर आना, भ्रम, बेहोशी और दुर्लभ मामलों में दौरे पड़ सकते हैं. यह आमतौर पर इंसुलिन या एंटीडायबिटिक दवा लेने वाले मरीजों में पाया जाता है, या जो बहुत लंबे समय तक फास्टिंग करते हैं या बहुत लंबे समय तक एक्सरसाइज करते हैं.

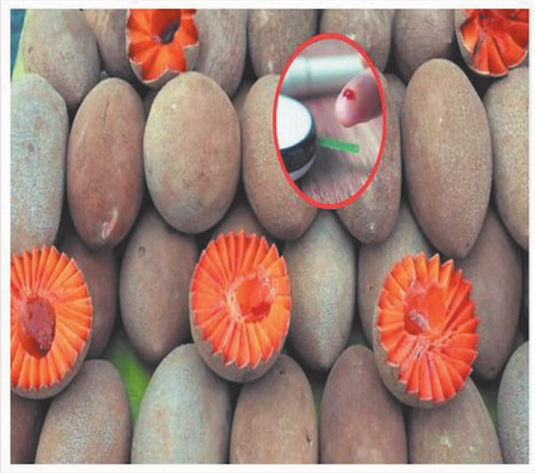

पैरों से पहचानें ब्लड शुगर बढ़ने के संकेत, दिखें तो तुरंत एक्शन की जरूरत

बीमारियों की बात करें तो डायबिटीज का नाम शायद सबसे पहले लिया जाएगा। बिजी और बिगड़ते लाइफस्टाइल, गलत खानपान के चलते शुगर के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती ही जा रही है। डायबिटीज यानि कि मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जो मरीज के शरीर को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। यह शरीर के बाकी अंगों को प्रभावित करती है। जब बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ती है तो शरीर कई तरह के संकेत देने लगता है। डायबिटीज के कुछ खास लक्षण पैरों में भी दिखने लगते हैं। चलिए आपको उन्हीं लक्षणों के बारे में बताते हैं जिन्हें पहचान कर आपको फौरन अलर्ट हो जाना चाहिए

डायबिटीज के कारण पैरों में दिखने वाले संकेत

डायबिटीज एक गंभीर रोग है जिसके लक्षण खासतौर पर पैरों में दिख सकते हैं जो हाई ब्लड शुगर के कारण उत्पन्न होते हैं। अगर डायबिटीज को समय रहते नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह पैरों की नसों और रक्त संचार को प्रभावित कर सकता है।

पैरों में सूजन : हाई ब्लड शुगर के कारण शरीर में लिक्विड संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे पैरों में सूजन आ सकती है। यह आमतौर पर खराब ब्लड सर्कुलेशन और किडनी की समस्याओं के कारण होता है।

नसों का नुकसान : डायबिटीज के कारण डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, जिससे पैरों में झुनझुनी, जलन या सुन्न होने की समस्या होती है। यह समस्या पैरों में घावों को महसूस करने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे चोट लगने पर देर से पता चलता है। पैरों की त्वचा शुष्क और फटी हुई दिख सकती है क्योंकि हाई ब्लड शुगर के चलते त्वचा की नमी कम हो सकती है। त्वचा में दरारें आने से बैक्टीरिया और फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है।

नाखूनों में फंगल संक्रमण : डायबिटीज के मरीजों में नाखूनों पर फंगल संक्रमण आम होता है, जिससे वे मोटे, पीले और कमजोर हो सकते हैं। इंफेक्शन बढ़ने पर नाखूनों में दर्द और असहजता हो सकती है।

पैरों में घाव या अल्सर : शुगर मरीज के पैर में चोट या कट लगने के बाद घाव जल्दी नहीं भरता, जिससे अल्सर बनने का खतरा रहता है क्योंकि पैरों में रक्त संचार की कमी होने लगती है और अगर ध्यान न दिया जाए तो यह गैंग्रीन जैसी गंभीर समस्या में बदल सकता है।

पैरों में बहुत ज्यादा दर्द और ऐंठन : ब्लड सर्कुलेशन खराब होने से पैरों में तेज दर्द, ऐंठन या भारीपन महसूस हो सकता है। यह संकेत रक्त वाहिकाओं में रुकावट की ओर भी इशारा कर सकते हैं।

डायबिटीज के मरीजों को पैरों की देखभाल कैसे करनी चाहिए?

पैरों की नियमित जांच करें, किसी भी कट, सूजन, लाल धब्बे या संक्रमण के संकेतों पर नजर रखें।

पैरों को मॉइश्चराइज करें। फटी त्वचा और रूखेपन से बचने के लिए मॉइश्चराइजर का इस्तेमाल करें।

आरामदायक जूते पहनें । टाइट या अनफिटेड जूतों से बचें, जो पैरों में चोट पहुंचा सकते हैं।

नाखूनों की सफाई का ध्यान रखें। नियमित रूप से नाखून काटें और संक्रमण से बचने के लिए साफ-सफाई रखें।

ब्लड शुगर कंट्रोल करें। नियमित रूप से ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाएं लें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

पीएम मोदी ने तारिक रहमान को दी जीत की बधाई

नईदिल्ली। बांग्लादेश के संसदीय चुनावों में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की ऐतिहासिक जीत के बाद दक्षिण एशियाई राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तारिक रहमान को इस अहम जीत पर बधाई दी और भविष्य में द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊँचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीएनपी की जीत दिखाती है कि बांग्लादेश के लोग रहमान की लीडरशिप पर भरोसा करते हैं, और कहा कि वह उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। सोशल मीडिया पर रहमान को टैग करते हुए एक पोस्ट में, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत हमेशा डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव और इनक्लूसिव बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में पार्लियामेंट्री चुनावों में बीएनपी को अहम जीत दिलाने के लिए मैं मिस्टर तारिक रहमान को दिल से बधाई देता हूं।

राहुल गांधी देश में गृहयुद्ध भड़काना चाहते हैं : गिरिराज

नईदिल्ली। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आलोचना करते हुए उन पर गलत सूचना फैलाने और देश में गृहयुद्ध भड़काने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद निशिकांत दुबे द्वारा गांधी के आचरण पर लगाए गए आरोपों के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सिंह ने कहा कि कांग्रेस नेता किसानों के मुद्दों और भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते पर जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के उन बयानों का हवाला दिया, जिनमें किसानों के हितों से समझौता न करने का आश्वासन दिया गया था। सिंह ने पत्रकारों से कहा कि किसानों का मुद्दा क्या? झूठ, राफेल की तरह। जनता में भ्रम फैलाना। देश के कृषि मंत्री चौहान और वाणिज्य मंत्री गोयल ने कहा कि किसानों के हितों से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। ये लोग सिर्फ देश में भ्रम फैलाना चाहते हैं। ये देश में गृहयुद्ध भड़काना चाहते हैं।

सपा प्रवक्ता मनोज एससी एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार

बाराबंकी। बाराबंकी के सफदरगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई दो दिन पहले दर्ज मुकदमे के आधार पर की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मनोज यादव को उस समय पकड़ा गया जब वे अपने कुछ साथियों के साथ सफदरगंज क्षेत्र से गुजर रहे थे। गिरफ्तारी के बाद उन्हें बड़ागांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां नियमानुसार उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया। एएसपी विकास चंद्र त्रिपाठी ने बताया कि सफदरगंज थाने में दो दिन पूर्व छेड़छाड़ और एससी-एसटी एक्ट के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। उसी प्रकरण में साक्ष्यों और विवेचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गिरफ्तारी स्थानीय पुलिस द्वारा की गई है। पिछले दो दिनों से मनोज यादव के संपर्क में न होने को लेकर चर्चा तेज थी।

स्टालिन ने तमिलनाडु की करोड़ों महिलाओं को दिए 5000 रुपये

चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को घोषणा की कि राज्य की कलाइनगर महिला अधिकार योजना के तहत महिला लाभार्थियों के खातों में अग्रिम रूप से 3,000 रुपये जमा कर दिए गए हैं। स्टालिन ने इस साल के अंत में होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों से पहले घोषणा की कि फरवरी, मार्च और अप्रैल महीनों के लिए 3,000 रुपये (प्रति माह 1,000 रुपये) की राशि आवंटित की गई है, साथ ही 2,000 रुपये की विशेष ग्रीष्मकालीन सहायता राशि भी उनके खातों में जमा कर दी गई है। एक्स पर एक पूर्व-रिकॉर्ड किए गए वीडियो क्लिप के साथ एक पोस्ट में, स्टालिन ने घोषणा की कि तमिलनाडु भर में 1.31 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में कुल 5,000 रुपये जमा किए गए हैं। स्टालिन ने विस्तार से बताते हुए कहा कि फरवरी, मार्च और अप्रैल महीनों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में 1,000 रुपये दिए गए थे, जबकि अतिरिक्त 2,000 रुपये बोनस के रूप में दिए गए थे।

पैसे लो, लेकिन वोट अपनी मर्जी से दो : दलपति विजय

चेन्नई। तमिलनाडु में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत में गर्माहट बढ़ गई है। इसी चुनावी गहमागहमी के बीच तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के प्रमुख और अभिनेता दलपति विजय ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए सत्ताधारी दल डीएमके सरकार पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही रैली के दौरान विजय ने मंच से लोगों को शपथ भी दिलाई। विजय ने अपने संबोधन में लोगों से कहा कि मेरा वोट मेरा अधिकार है। कोई हमें खरीद नहीं सकता। हमारा वोट 'सीटी' के लिए है। बता दें कि यहां 'सीटी' उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह है। इसके साथ ही विजय ने अपने संबोधन में सीएम स्टालिन पर निशाना भी साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मेरे लिए एसओपी का मतलब है स्टालिन ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव के समय लोगों को पैसे बांटे जाते हैं। विजय ने कहा कि अगर कोई हजारों रुपये देने आए तो ले लें, क्योंकि वह आपका ही पैसा है। लेकिन पैसा लेने के बाद वोट अपनी मर्जी से दीजिए और ऐसे लोगों को 'सीटी बजाकर' विदा कर दीजिए।

स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र पहचान, गुलामी से मुक्त निशानः पीएम मोदी

नईदिल्ली । शुक्रवार को प्रधानमंत्री कार्यालय के नए भवन 'सेवा तीर्थ' और कर्तव्य भवन के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय प्रशासन ने विशेष रूप से सेवा तीर्थ स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया, जिसे प्रशासनिक और नागरिक दृष्टि से गौरवपूर्ण कदम बताया जा रहा है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कार्यालय की आधुनिक सुविधाओं, डिजिटल कार्य प्रणाली और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने वाले उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया। नए भवनों का उद्देश्य सरकारी कामकाज को पारदर्शी और कुशल बनाना है। उद्घाटन समारोह में उच्च स्तर के

अधिकारी, वरिष्ठ प्रशासनिक पदाधिकारी और मीडिया प्रतिनिधि मौजूद रहे।

'सेवा तीर्थ' का निर्माण प्रशासनिक कार्यकुशलता और जनता को सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। इसके साथ ही कर्तव्य भवन सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को बेहतर कार्य वातावरण उपलब्ध कराने के लिए तैयार किया गया है। इस अवसर पर जारी किए गए डाक टिकट और सिक्का का उद्देश्य जनता में सरकारी योजनाओं और प्रशासनिक सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना बताया गया है। अधिकारियों ने बताया कि स्मारक डाक टिकट और सिक्का न केवल स्मृति चिन्ह के रूप में महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यह भारत में सार्वजनिक सेवा और प्रशासनिक उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में भी मूल्य रखते हैं।विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के कदम नागरिकों में सरकारी कार्य प्रणाली के प्रति विश्वास बढ़ाने में सहायक होंगे। उद्घाटन समारोह के दौरान अधिकारियों ने यह भी बताया कि भवन में अत्याधुनिक सम्मेलन कक्ष, डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्मार्ट कार्यालय सुविधाएं मौजूद हैं। इस कार्यक्रम से यह संदेश भी गया कि सरकारी भवनों के निर्माण और उन्हें प्रभावी ढंग से संचालित करने का उद्देश्य केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि जनता और प्रशासन के बीच की दूरी कम करना और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाना है।

विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा भारतः गोयल

नईदिल्ली । ग्लोबल बिजनेस समिट में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री गोयल ने जोर दिया कि केंद्र सरकार का ध्येय विकास भी, विरासत भी है और नीतियों से लेकर प्रक्रियाओं तक आम लोगों व कारोबारियों पर अनुपालन का बोझ कम करना प्राथमिकता है। केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि भारत ने अपनी शर्तों पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) किए हैं। खास तौर पर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन के साथ समझौते का उल्लेख कर उन्होंने कहा कि इन देशों ने भारत में 100 अरब डॉलर के एफडीआई का कानूनी वचन दिया है। तय समय में निवेश न होने पर भारत छूट वापस ले सकता है, ऐसा प्रावधान पहले दुनिया के किसी समझौते में कभी नहीं देखा गया। उन्होंने कहा कि सभी एफटीए तीन सिद्धांतों—विश्वास, पारदर्शिता और समयबद्ध निश्चितता—पर आधारित हैं और इन समझौतों से भारत के लिए दुनिया के 70 प्रतिशत बाजार तक पहुंच खुली है। केंद्रीय मंत्री गोयल के अनुसार भारत वर्तमान में करीब 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है, जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा और 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की क्षमता रखता है।अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि भारत ने हर डील अपनी शर्तों पर की है। उन्होंने तर्क दिया कि विकसित

देशों की उच्च पर कैपिटा आय के कारण वे भारतीय बाजार में सस्ते उत्पादों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते।

इसलिए भारत केवल जरूरत की वस्तुएं ही आयात करेगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत ने किसी भी एफटीए में डेयरी जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को नहीं खोला। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ या अमेरिका—किसी के लिए भी डेयरी सेक्टर नहीं खोला गया, ताकि छोटे किसानों के हित सुरक्षित रहें। इतना ही नहीं केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि एफटीए के बाद यूरोप और अमेरिका के बाजार भारतीय टेक्सटाइल उत्पादों के लिए अधिक सुलभ हुए हैं। इससे 70-80 लाख रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है। उन्होंने बजट में डेटा सेंटर प्रोत्साहनों को निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और नौकरियों के लिए बूस्टर बताया। साथ ही कहा कि एआई इंसानों की जगह नहीं लेगा, बल्कि नए अवसर पैदा करेगा।

सांसद स्वाति मालीवाल ने संसद में स्वच्छता और सिविक सेंस का मुद्दा

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने संसद के उच्च सदन में स्वच्छता और सिविक सेंस का मुद्दा उठाते हुए कहा कि देश को साफ रखना केवल सरकार की नहीं, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। राज्यसभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि शहरों में सड़कों पर कूड़ा, जाम

फुटपाथ, खराब पब्लिक टॉयलेट और सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी आम दृश्य बन चुके हैं। उन्होंने माना कि राज्य सरकारें और नगर निगम अपनी जिम्मेदारी निभाने में कई बार नाकाम रहे हैं, लेकिन नागरिकों की मानसिकता भी बड़ी समस्या है।

सांसद मालीवाल ने कहा, कि हम अपना घर साफ रखते हैं, लेकिन घर से बाहर निकलते ही सड़क को अपना नहीं मानते। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि लोग पार्कों में कूड़ा छोड़ देते हैं, पानी की बोतलें सड़क पर फेंक देते हैं और सार्वजनिक स्थानों पर गुटखा थूकते हैं। उन्होंने दिल्ली के राजीव चौक मेट्रो स्टेशन का जिक्र करते हुए कहा कि वहां धक्का-मुक्की और लाइन तोड़ना आम बात है। इसके अलावा पर्यटन स्थलों और पहाड़ी इलाकों में गंदगी फैलाने की प्रवृत्ति पर भी चिंता जताई।सांसद मालीवाल ने कहा कि विदेशों में साफ-सफाई की तारीफ करने वाले लोगों को समझना चाहिए कि वहां लोग सार्वजनिक स्थानों को अपना मानते हैं। उन्होंने जापान का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां बच्चे अपना क्लासरूम खुद साफ करते हैं।इसके साथ ही, उन्होंने भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों की तारीफ करते हुए कहा कि वहां ट्रैफिक नियमों का पालन, नो हॉर्निंग और त्योहारों में जीरो प्लास्टिक जैसी पहलें अनुकरणीय हैं।

एआई एवं क्लाउड कंप्यूटिंग प्रतिस्पर्धा अब पृथ्वी पर नहीं अंतरिक्ष में होगी

नईदिल्ली । भारतीय कंपनी अग्निकुल कॉसमॉस वैश्विक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) एवं क्लाउड कंप्यूटिंग की दौड़ के लिए तैयारी कर रही है। इसके लिए प्रतिस्पर्धा पृथ्वी पर नहीं अंतरिक्ष में होगी। चेन्नई की स्पेसटेक स्टार्टअप जल्द ही अंतरिक्ष आधारित एआई डेटा सेंटर को होस्ट करने के लिए पूरी तरह तैयार है। वह इस अवधारणा पर काम करने वाली एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स, गूगल और ऐक्सीअम जैसी खास कंपनियों की जमात में शामिल होने जा रही है। पहली बार कोई भारतीय कंपनी ऑर्बिटल डेटा सेंटर को सुगम बनाने के लिए काम कर रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर भी पहली बार कोई कंपनी अपने प्रक्षेपण यान के एक्स्टेंडेबल अपर स्टेज को डेटा सेंटर होस्ट करने वाली सैटेलाइट बस के तौर पर इस्तेमाल करने की पेटेंट वाली

प्रौद्योगिकी उपलब्ध करा रही है। कंपनी ने एआई डेटा सेंटर को रखने की अपनी क्षमता की ही घोषणा नहीं की है, बल्कि बेंगलुरु की कंपनी नीवक्लाउड को अपने पहले ग्राहक के रूप में शामिल भी कर लिया है।अनुबंध के मुताबिक नीवक्लाउड के एआई सुपरक्लाउड प्लेटफॉर्म द्वारा विकसित कक्षा आधारित एआई डेटा सेंटर मॉड्यूल को अग्निकुल अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करेगी।

खेल
प्रमुख समाचार

टी20 विश्वकप में जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हराया

कोलंबो। टी20 विश्वकप 2026 का पहला बड़ा उलटफेर हो चुका है। जिम्बाब्वे ने इस संस्करण के 19वें मुकाबले में 2021 की टी20 विश्वकप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 23 रन से हरा दिया है। यह मुकाबला कोलंबो के प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया। जिम्बाब्वे ने 20 ओवर में दो विकेट गंवाकर 169 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पूरी पारी 19.3 ओवर में 146 रन पर सिमट गई। यह जिम्बाब्वे टीम की ऑस्ट्रेलिया पर टी20 में दूसरी जीत है। इससे पहले जिम्बाब्वे ने 2007 टी20 विश्वकप में ऑस्ट्रेलिया को पांच विकेट से हराया था। दोनों के बीच अब तक चार बार आमना-सामना हुआ है। इसमें से दो बार ऑस्ट्रेलियाई टीम और दो बार जिम्बाब्वे की टीम जीती है। सिकंदर रजा की टीम का टी20 विश्वकप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 100 प्रतिशत जीत का रिकॉर्ड है। यानी अब तक कंगारू जिम्बाब्वे की टीम को इस टूर्नामेंट में हरा नहीं पाए हैं।

जिम्बाब्वे को पहला झटका आठवें ओवर में 61 के स्कोर पर लगा। मार्कस स्टोइनिस ने तादिवानाशे मरुमानी को जोश इंग्लिस के हाथों कैच कराया। उन्होंने 21 गेंद में सात चौके की मदद से 35 रन बनाए। जिम्बाब्वे को दूसरा झटका रेयान बर्ल के रूप में लगा। वह 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट हुए। बर्ल ने 30 गेंद में चार चौके की मदद से 35 रन बनाए। बर्ल को कैमरन ग्रीन ने पवेलियन भेजा। ब्रायन बेनेट 56 गेंद में सात चौके की मदद से 64 रन बनाकर नाबाद रहे। वहीं, कप्तान सिकंदर रजा ने भी 13 गेंद में दो चौके और एक छक्के की मदद से नाबाद 25 रन बनाए। दोनों ने चौथे विकेट के लिए 24 गेंद में नाबाद 38 रन की साझेदारी की। जिम्बाब्वे की ओर से मुजरबानी ने चार और इवांस ने तीन विकेट झटके। मसाकदजा और बर्ल को एक-एक विकेट मिला।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स ने 1048 अंक का गोता लगाया; निफ्टी 25471 पर बंद

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों में जारी गिरावट का असर शुक्रवार (13 फरवरी) को भारतीय शेयर बाजार पर भी साफ दिखा और बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी-50 और सेंसेक्स 1 प्रतिशत से ज्यादा गिरकर बंद हुए। इंडेक्स हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल), आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक के शेयरों में बिकवाली ने भी बाजार को नीचे को नीचे की तरफ खींचा। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स बड़ी गिरावट के साथ 82,902 अंक पर खुला। खुलने के बाद इंडेक्स में गिरावट और बढ़ गई। अंत में यह 1048.16 अंक या 1.25 फीसदी की गिरावट लेकर 82,626.76 पर बंद हुआ। इसी तरह, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी बड़ी गिरावट में खुला और खुलने के कुछ ही देर में 25,500 के लेवल से नीचे चला गया। अंत में यह 336.10 अंक या 1.30 फीसदी गिरकर 25,471 पर बंद हुआ।

वित्तवर्ष 26 में टैक्स बचत का आसान रास्ता

नईदिल्ली। अगर आप बिना जोखिम के निवेश कर टैक्स बचत करना चाहते हैं, तो पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट स्कीम आपके लिए एक मजबूत विकल्प हो सकती है। यह योजना बैंक एफडी की तरह काम करती है, लेकिन सरकारी गारंटी और स्थिर रिटर्न के कारण इसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। खास बात यह है कि 5 साल की अवधि वाले टाइम डिपॉजिट पर आयकर अधिनियम की धारा 8सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ लिया जा सकता है। देश में फिलहाल दो तरह की टैक्स व्यवस्था लागू है, न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम। धारा 80सी के तहत मिलने वाली टैक्स छूट का लाभ केवल पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनने पर ही मिलता है। इसलिए निवेश से पहले यह तय कर लें कि आप कौन सी टैक्स प्रणाली अपना रहे हैं।

सीपीआई का बेस ईयर बदलने के बीच महंगाई शांत

नईदिल्ली। महंगाई को मापने के तरीके में बड़ा बदलाव हुआ है, लेकिन राहत की बात यह है कि नई गणना के बाद भी महंगाई काबू में दिख रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई का बेस ईयर बदला गया है, ताकि लोगों के बदलते खर्च के पैटर्न को बेहतर तरीके से दिखाया जा सके। इसके बावजूद जनवरी के आंकड़े बताते हैं कि महंगाई फिलहाल ज्यादा चिंता की वजह नहीं बनी है। सीपीआई का बेस ईयर 2012 से बदलकर 2024 कर दिया गया है। यह बदलाव 2023-24 के घरेलू खपत सर्वे के आधार पर किया गया है, जिससे आज की वास्तविक खर्च आदतों को शामिल किया जा सके। नई सीरीज में ग्रामीण हाउसिंग, ओटीटी सेवाएं और कुछ डिजिटल सामान जोड़े गए हैं, जबकि पुराने हो चुके सामान जैसे वीसीआर, रेडियो और टेप रिकॉर्डर हटा दिए गए हैं। साथ ही कई चीजों की श्रेणी भी बदली गई है।

सिल्वर और कॉपर की कीमतों पर नया अनुमान

नईदिल्ली। पिछले कुछ महीनों में सिल्वर और कॉपर की कीमतों में जोरदार उछाल देखने को मिला लेकिन अब एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले समय में इन धातुओं में बड़ी तेजी की बजाय ठहराव या गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं सिल्वर की कीमतें डॉलर की चाल के हिसाब से एक तय दायरे में रह सकती हैं। खासकर कॉपर की तेजी का बड़ा कारण मजबूत मांग नहीं, बल्कि सप्लाई से जुड़ी समस्याएं रही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक, हालिया उछाल के पीछे कई बड़ी खदानों में उत्पादन बाधित होना मुख्य कारण रहा। कॉपर 8,000 डॉलर से बढ़कर करीब 14,000 डॉलर प्रति मीट्रिक टन तक पहुंच गया। दुनिया की कई बड़ी खदानों में प्रोडक्शन संकट आया। हालांकि, वैश्विक स्तर पर कॉपर की वास्तविक कमी नहीं है।

रिजर्व करंसी' का अपना दर्जा छोड़ने को डॉलर तैयार नहीं

नारायण रामचंद्रन

2026 की शुरुआत के साथ ही 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। पहली घटना यह थी कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए 'मजबूत युआन' का स्पष्ट आह्वान किया, वहीं दूसरी ओर, अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने गिरते डॉलर को लेकर जताई जा रही चिंताओं को 'नहीं, यह तो बढ़िया है' कह कर खारिज कर दिया। यह सच है कि शी ने यह बात 2024 में एक बंद मंच पर कही थी, लेकिन चीनी अधिकारियों ने इसे इसी साल सार्वजनिक किया। यह भी सच है कि ट्रम्प लगभग 4 दशकों में डॉलर की बात करने वाले पहले अमरीकी राष्ट्रपति हैं।पहले अमरीकी डॉलर के विभिन्न ऐतिहासिक चक्रों पर एक संक्षिप्त नजर डालें। सबसे पहला चक्र 1971 में राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत स्वर्ण मानक और डॉलर की स्वर्ण में परिवर्तनीयता को निलंबित करने की चौंकाने वाली घोषणा से शुरू होता है। तब से, डॉलर के 7 प्रमुख चक्र रहे हैं। पहला, 1971-1978: स्वर्ण मानक छोड़ने के बाद अस्थिरता। दूसरा, 1978-1985: डॉलर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। तीसरा चरण, 1985-1992: प्लाजा समझौता और व्यापारिक सांझेदारों के सहयोग से डॉलर के मूल्य में नियोजित अवमूल्यन।

चौथा चरण, 1992-2002: मजबूत डॉलर का युग, जिसमें अमरीका एकमात्र वैश्विक महाशक्ति था। पांचवां चरण, 2002-2012: अमरीका द्वारा महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति में ढील देने के कारण डॉलर का मूल्य कम हुआ, जबकि उभरते बाजारों में तेजी आई।

छठा चरण, 2012-2022: मजबूती का एक दशक, जो 2022 के आसपास उच्चतम स्तर पर पहुंचा। सातवां चरण, 2022-2026=

डॉलर नए शिखर पर पहुंचा लेकिन 2022 के मध्य में गिरावट शुरू हुई जो 2025 में और तेज हो गई।

आज, डी.एक्स.वाई. डॉलर सूचकांक (छह मुद्राओं की एक टोकरी के मुकाबले) अपने 2022 के उच्चतम स्तर से लगभग 13 प्रतिशत नीचे है, अपने 2008 के न्यूनतम स्तर से 30 प्रतिशत ऊपर है और पूर्ण अवधि के रुझान के ठीक मध्य में है। साथ ही, सोना, जिसे कभी-कभी 'एंटी-डॉलर' कहा जाता है और चांदी, तांबा और प्लैटिनम जैसी अन्य धातुएं हाल ही में अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं (हालिया बिकवाली के साथ)। इससे कुछ विश्लेषकों ने इसे 'डॉलर का अवमूल्यन' कहना शुरू कर दिया है। मुद्राओं के संदर्भ में, अवमूल्यन एक गंभीर शब्द है। इस शब्द के लागू होने के लिए निम्नलिखित चारों शर्तों का पूरा होना आवश्यक है-एक, मुद्रा आपूर्ति में भारी वृद्धि, जिसे आमतौर पर एम2 वृद्धि द्वारा मापा जाता है; दो, बड़ा राजकोषीय और चालू खाता घाटा; तीन, आसान मौद्रिक नियंत्रण परिस्थितियां, जो आमतौर पर मात्रात्मक सहजता की नीति द्वारा चिह्नित होती हैं और चौथी, देश के आर्थिक प्रबंधन में कम विश्वास।

इन चार मापदंडों के आधार पर, आज अमरीका की स्थिति कुछ इस प्रकार है। एम2 द्वारा मापी गई वार्षिक मुद्रा आपूर्ति वृद्धि 5 प्रतिशत है, जो काफी सामान्य है। अमरीका का राजकोषीय घाटा काफी अधिक है (2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 5.5 प्रतिशत अनुमानित) और इसका राष्ट्रीय ऋण 39 ट्रिलियन डॉलर है। एक असामान्य स्थिति यह है कि इसमें से 9 ट्रिलियन डॉलर का पुनर्वित्तपोषण 2026 में होना है, जिससे बॉन्ड यील्ड पर दबाव बढ़ सकता है। अमरीका सकारात्मक वास्तविक दरों और मात्रात्मक सख्ती के संयोजन के साथ मध्यम रूप से सख्त मौद्रिक स्थितियों में काम कर रहा है। हाल के समय में डॉलर के 'सामान्यीकरण' की प्रक्रिया तेज हुई है और आज अमरीका को मुद्रा अवमूल्यन का खतरा नहीं है। यह मुख्य रूप से अमरीकी अर्थव्यवस्था के प्रति लोगों की भावना पर निर्भर करता है। प्रबंधन ने डॉलर को कमजोर कर दिया है। पिछले करीब एक साल से भारतीय रुपया उन मुद्राओं में से एक रहा है, जिनकी कीमत डॉलर के कमजोर होने के कारण कम हुई है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक संपन्न

सिद्धांतों के अनुरूप हो सभी गतिविधियों का संचालन : मुख्यमंत्री साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की 16वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में बोर्ड की 15वीं बैठक के पालन प्रतिवेदन तथा नवीन एजेंडों पर चर्चा उपरांत प्रस्तावों को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के निर्णय हेतु प्रेषित करने पर सहमति बनी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि वन्यजीव हमारी प्रकृति की अमूल्य धरोहर हैं और उनके संरक्षण-संवर्धन के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए सतत निगरानी, अवैध गतिविधियों पर रोक तथा उनकी सुरक्षा के लिए जनभागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही, वनों के आसपास रहने वाले ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाने और युवाओं की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने न्यूनतम हस्तक्षेप के सिद्धांत को अपनाते हुए अत्यावश्यक कार्यों को ही वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास में बिना किसी छेड़छाड़ के पूर्ण करने पर बल दिया। उन्होंने सह-अस्तित्व के सिद्धांतों के अनुरूप सभी गतिविधियों के संचालन की बात कही।

बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति के गठन को मंजूरी दी गई। स्थायी समिति का गठन वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री की अध्यक्षता में किया जाएगा, जिसमें 11 अन्य सदस्य शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि वन्य प्राणियों की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में होने वाले कार्यों के प्रस्तावों पर राज्य वन्यजीव बोर्ड का अभिमत अनिवार्य होता है। बोर्ड की बैठकों के बीच अधिक अंतराल के कारण प्रस्तावों की स्वीकृति में विलंब की स्थिति बनती है। स्थायी समिति के गठन से वैधानिक मंजूरियों के त्वरित निपटान तथा वन्यजीव प्रबंधन से संबंधित मुद्दों के शीघ्र निराकरण में सहायता मिलेगी।

बैठक में उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व अंतर्गत बरबांधा जलाशय में बांध एवं नहरों के जीर्णोद्धार एवं नवीन कार्य, पीएम जनमन योजना के अंतर्गत कबीरधाम जिले के कवर्धा वनमंडल में पंडरीपानी मेन रोड से सौरु तक मार्ग मजबूतीकरण, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने से संबंधित 6 प्रस्ताव, सेमरसोत अभ्यारण्य में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने, उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में सीआरपीएफ कैंप की स्थापना तथा उदंती-सीतानदी टाइगर रिजर्व में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के प्रस्तावों का अनुमोदन कर उन्हें राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्वीकृति हेतु प्रेषित करने पर सहमति दी गई।कार्यक्रम में वन मंत्री केदार कश्यप, विधायक धर्मजीत सिंह, मुख्य सचिव विकास शील, अपर मुख्य सचिव श्रीमती ऋचा शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख व्ही. श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) अरुण कुमार पाण्डेय सहित बोर्ड के अन्य सदस्य एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे।

एनटीपीसी द्वारा इंडियन पावर स्टेशन ओ एंड एम कॉन्फ्रेंस 2026 का आयोजन आज से

रायपुर। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत विद्युत कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड 13 से 15 फरवरी तक इंडियन पावर स्टेशन ओ एंड एम कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने जा रही है। यह तीन दिवसीय सम्मेलन विद्युत क्षेत्र के विशेषज्ञों और पेशेवरों को संवाद, सीखने और सहयोग के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा। इस अवसर पर विद्युत मंत्रालय तथा विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

यह वार्षिक सम्मेलन एनटीपीसी की यात्रा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जो वर्ष 1982 में सिंगरौली में इसकी पहली थर्मल इकाई के वाणिज्यिक संचालन की स्मृति को चिह्नित करता है। यह उपलब्धि भारत के विद्युत क्षेत्र में परिचालन उत्कृष्टता की नींव रखने वाला ऐतिहासिक मील का पत्थर थी।

वर्षों के दौरान आईपीएस एक विश्वसनीय मंच के रूप में विकसित हुआ है, जहाँ नीति-निर्माता, उद्योग विशेषज्ञ, संयंत्र संचालक, निर्माता, शोधकर्ता और शिक्षाविद एकत्र होकर अनुभव साझा करते हैं, व्यावहारिक जानकारियों का आदान-प्रदान करते हैं और देश में विद्युत उत्पादन की दिशा तय करने के लिए सामूहिक रणनीति बनाते हैं।

ऊर्जा सुरक्षा और ग्रिड स्थिरता सुनिश्चित करने में तापीय ऊर्जा की निरंतर महत्ता को रेखांकित करता है, विशेष रूप से उस समय जब भारत स्वच्छ और विविधीकृत ऊर्जा मिश्रण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गुणवत्ता और विश्वसनीयता भरोसेमंद बिजली आपूर्ति के मूल स्तंभ हैं, और यह सम्मेलन साझा सीख और व्यवहारिक अनुभवों के माध्यम से इन स्तंभों को और मजबूत करने पर केंद्रित रहेगा।

तीन दिवसीय सम्मेलन में तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें क्षेत्र के विशेषज्ञ परिचालन चुनौतियों, बदलती आवश्यकताओं और उभरते अवसरों पर विचार-विमर्श करेंगे। चर्चा के प्रमुख विषयों में लचीला संयंत्र संचालन, सुरक्षा, एसेट प्रबंधन, जल एवं ईंधन प्रबंधन, डिजिटल अनुप्रयोग, दक्षता में सुधार तथा परमाणु ऊर्जा, हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा और भंडारण समाधान जैसे नए ऊर्जा मार्गों की भूमिका शामिल है।आईपीएस 2026 को अभूतपूर्व प्रतिक्रिया मिली है। कुल 466 से अधिक लेखकों ने तकनीकी शोध-पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें नवीनतम प्रगति, सर्वोत्तम प्रथाएँ और विद्युत उत्पादन के भविष्य को आकार देने वाले नवाचार शामिल हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण की चतुर्थ बैठक आयोजित

रायपुर। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तथा अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य वेटलैण्ड प्राधिकरण श्री केदार कश्यप की अध्यक्षता में प्राधिकरण की चतुर्थ बैठक का आयोजन अरण्य भवन,अटल नगर में किया गया। बैठक में मुख्य सचिव एवं प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विकासशील, अपर मुख्य सचिव वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ऋचा शर्मा, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वी. श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) अरूण कुमार पाण्डेय, सचिव आवास एवं पर्यावरण विभाग, सदस्य सचिव तथा अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

यह प्राधिकरण राज्य के आर्द्रभूमियों के संरक्षण, प्रबंधन, उनके पारिस्थितिक स्वरूप को बनाए रखने और उन पर होने वाली गतिविधियों के नियमन के लिए उत्तरदायी है। यह प्राधिकरण गिधवा-परसदा और कोपरा जैसे जलाशयों के संरक्षण, प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा, और जिला स्तर पर बनी समितियों के माध्यम से प्रबंधन की निगरानी करता है।

बैठक में रामसर सचिवालय से प्राप्त कोपरा जलाशय के रामसर प्रमाणपत्र का विमोचन किया गया। इसके साथ ही कोपरा जलाशय तथा गिधवा-परसदा वेटलैण्ड काम्प्लेक्स के लोगों का भी अनावरण किया गया। बैठक में राज्य के वेटलैण्ड क्षेत्रों के संरक्षण, संवर्धन और विकास पर विस्तार से चर्चा की गई। यह भी निर्णय लिया गया कि विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय से वेटलैण्ड क्षेत्रों के संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय समुदायों को जागरूक किया जाएगा, ताकि प्राकृतिक जल स्रोतों और जैव विविधता का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

ट्रैफिक जाम से राहत, रिंग रोड नंबर 1 के चौड़ीकरण को एनएचएआई की मंजूरी

नई दिल्ली/रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी में लंबे समय से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिंग रोड नंबर 1, यानी ह॥-53 के किनारे स्थित सर्विस रोड के चौड़ीकरण को आधिकारिक मंजूरी दे दी है।

यह परियोजना रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल के सतत प्रयासों और वकालत का परिणाम मानी जा रही है। ह॥ द्वारा इस कार्य के लिए ?99.72 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। रायपुर की रिंग रोड नंबर 1 शहर की प्रमुख यातायात धमनियों में से एक है। वर्षों पहले इसे शहर के बाईपास के रूप में विकसित किया गया था, लेकिन तेज़ी से हुए शहरी विस्तार के कारण अब यह मार्ग घनी आबादी, आवासीय कॉलोनियों और वाणिज्यिक गतिविधियों से घिर चुका है। बढ़ते वाहनों के दबाव के चलते मौजूदा सर्विस रोड की सीमित चौड़ाई यातायात के लिए बाधा बन रही थी। वर्तमान में लगभग 5 से 5.5 मीटर चौड़ी सर्विस रोड पर स्थानीय यातायात और भारी राजमार्ग वाहनों का मिश्रण अक्सर भीषण जाम और दुर्घटना की आशंका को जन्म देता है।इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्र सरकार और संबंधित विभागों के समक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाया। पिछले दो वर्षों में उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कई उच्च-स्तरीय आवेदन प्रस्तुत किए। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को लिखे पत्रों में अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि शहर की भीड़भाड़ कम करने और सुचारु यातायात व्यवस्था के लिए सर्विस रोड का चौड़ीकरण अत्यधिक आवश्यक है।

शिक्षक भर्ती की मांग: मंत्रालय का घेराव करने निकले डीएड अभ्यर्थी

रायपुर। शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर पिछले दो माह से आमरण अनशन पर बैठे डीएड अभ्यर्थियों ने आज मंत्रालय घेराव के लिए कूच किया। हालांकि पुलिस ने रास्ते में ही उन्हें रोक दिया। अभ्यर्थियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने ट्रक को बैरिकेड के रूप में खड़ा कर दिया, जिससे मौके पर तनाव की स्थिति बन गई।

बताया जा रहा है कि अभ्यर्थी लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने और लंबित पदों पर नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। उनका आमरण अनशन तूता धरना स्थल पर जारी है। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक शासन की ओर से कोई ठोस पहल नहीं की गई है।मंत्रालय घेराव की घोषणा के बाद प्रशासन पहले से सतर्क था। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। जैसे ही अभ्यर्थियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें रोकते हुए बैरिकेडिंग कर दी। इस दौरान अभ्यर्थी नारेबाजी करते रहे और अपनी मांगों पर अड़े रहे। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। अभ्यर्थियों का आरोप है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों के बावजूद शिक्षा विभाग रिक्त पदों लगभग 2300 पर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं कर रही है। वहीं प्रशासन ने शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर करीब दो महीने से डीएड अभ्यर्थियों का आमरण अनशन जारी है। यह आंदोलन सहायक शिक्षक भर्ती 2023 के शेष रिक्त पदों लगभग 1300-2300 पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर चल रहा है।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

देश की कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे गृह मंत्री : शुक्ला

रायपुर। गृहमंत्री विजय शर्मा के द्वारा 2 साल में गृह विभाग की जो उपलब्धियां बताई गई है वह केवल कागजी और मनगढ़त है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि गृह मंत्री प्रदेश की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था के बारे में मौन रहे। राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद आधा दर्जन से अधिक बार जनता बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में सड़को

पर उतर कर हिंसक आंदोलन करने को मजबूर हुई है। बलौदाबाजार में एसपी कलेक्टर कार्यालय जला दिये गये, कवर्धा में एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया, तमनार, बलरामपुर, सूरजपुर में जनता ने बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर उतरी, जब गृह मंत्री प्रेस कांफ्रेंस लेकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे तो कोण्डागांव में लोग हिंसक आंदोलन कर रहे थे।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि गृह मंत्री कहते है उन्होंने 34 बंग्लादेशी नागरिकों को प्रदेश से बाहर निकाला, उनकी केंद्र सरकार कहती है देश में कोई घुसपैठिये नहीं है। सही कौन बोल रहा, मोदी सरकार या विजय शर्मा? देश में 12 सालों से भाजपा की सरकार है। ऐसे में देश के हृदय स्थल में घुसपैठियों का पहुंचना क्या केंद्र की मोदी सरकार की नाकामी नही है?

गरीब बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीन लिया: ठाकुर

रायपुर। आरटीई में इस वर्ष 24 हजार से अधिक सीट कम होने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार पैसा बचाने आरटीई के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों की नर्सरी, पीपी-वन एवं पीपी-टू में भर्ती के नियम खत्म कर सीधा क्लास वन में ही भर्ती की अनिवार्यता कर गरीब बच्चों से शिक्षा का अधिकार

छीन लिया है। इस नियम से आरटीई के तहत पिछले वर्ष की तुलना में 44,173 सीट पर भर्ती की जगह अब मात्र 19 हजार 466 सीटों पर ही भर्ती होगी, मतलब 24 हजार से अधिक सीट खत्म कर दी गई। इससे गरीबों को अपने बच्चों को निजी स्कूलों में नर्सरी व पीपी-वन पढ़ाने मोटी रकम खर्च करना पड़ेगा। ताकि पीपी-टू के बाद उसी स्कूल में आरटीई के तहत बच्चे का एडमिशन हो सके।प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने शिक्षा का अधिकार कानून बनाये तो स्पष्ट रूप से नियम बनाया की निजी स्कूलों में भर्ती नर्सरी से क्लास वन तक होगी। भाजपा सरकार ने आरटीई में नियम बदलने अपने ही पूर्व सरकार के 2014 के लागू फैसले को बदल दिया। अब गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा कैसे मिलेगी।

7 लाख किसानों का धान नहीं खरीदा गया: साहू

रायपुर। रायपुर स्थित प्रदेश कार्यालय में आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश महासचिव वदूद आलम ने कहा कि भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण खरीफ फसल धान को प्रदेश के 7 लाख किसान अपनी धान बेचने से वंचित रह गये जिससे प्रदेश के लाखो किसानों के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया है। भाजपा सरकार ने इस वर्ष प्रदेश के 7 लाख से

अधिक किसानों का 7130 करोड़ रू. का लगभग 23 लाख टन धान नहीं खरीदा। सरकार ने 2.5 लाख पंजीकृत किसानों से उनका धान नहीं खरीदा और एग्रीस्टेक पोर्टल की परेशानियों तथा रकबा समर्पण के कारण 5 लाख से अधिक किसान अपना धान नहीं बेच पाये। सरकार ने पहले दिन से ही कम से कम किसानों से धान खरीदने का षडयंत्र रचा जिसमें वह सफल भी साबित हुई। जिसके कारण अन्नदाता अपने फसल की पूरी कीमत पाने से वंचित हो गये है। सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण किसान परेशान हो गये है। फसल के लिये लिया गया ऋण भी वह अदा कर पाने की स्थिति में नहीं है ही। अधिकांश किसानों वर्ष भर का खर्चा भी धान की फसल से ही चलता है। सरकार ने उनका धान नहीं खरीद कर आर्थिक परेशानी में लाकर खड़ा कर दिया है।

ट्रेड डील में राहुल गांधी झूठा बयान दे रहे हैं : डॉ. मिश्रा

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजयशंकर मिश्रा ने ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को झूठ का एक और शर्मनाक प्रदर्शन बताते हुए कहा है कि राहुल गांधी एक आदतन झूठ बोलने वाले व्यक्ति हैं। उन्हें न तो माँ भारती की कोई चिंता है और न ही हमारे किसानों और युवाओं के कल्याण की। डॉ. मिश्रा ने भाजपा प्रवेश के ऑफर संबंधी बयान देकर झूठ की

राजनीति करने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर भी तीखा कटाक्ष कर कहा कि कांग्रेस की अब यही पहचान है कि गुरु और चेला झूठ बोलने में एक समान हैं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने झूठ बोलने और निराधार आरोप लगाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वह अपनी फर्जी कहानियों से हमारे किसानों को गुमराह कर रहे हैं और हमारे अन्नदाताओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ हाल ही में हुए व्यापार समझौते में, किसानों के हितों को सर्वोपरि रखा गया है और उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि बासमती चावल, फल, मसाले, चाय, समुद्री उत्पाद और कई अन्य उत्पादों को नए बाजार मिलेंगे, जिससे निर्यात बढ़ेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी।

गुरुकुल परंपरा व नैतिक शिक्षा के समन्वय पर बल : सिन्हा

रायपुर। आधुनिक शिक्षा के साथ नैतिक मूल्यों एवं शिष्टाचार का समावेश अत्यंत आवश्यक है। गुरुकुल परंपरा की मूल भावना को अपनाते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना समय की आवश्यकता है।उक्त विचार श्री रूपनारायण सिन्हा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योग आयोग द्वारा पीएम श्री प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शाला अखरा (पाटन), जिला दुर्ग के वार्षिकोत्सव एवं सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए व्यक्त किए गए।

गुरुकुल परंपरा एवं नैतिक शिक्षा के समन्वय पर बल- श्री रूपनारायण सिन्हाश्री सिन्हा ने कहा कि पीएम श्री विद्यालय की संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में की गई है, जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक सुविधायुक्त, गुणवत्तापूर्ण एवं समग्र शिक्षा प्रदान करना है। इस पहल के अंतर्गत शिक्षा के साथ-साथ संगीत, खेल एवं योग जैसी गतिविधियों को भी विशेष महत्व दिया जा रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता जितेंद्र वर्मा द्वारा की गई। अतिथियों का शाला प्रबंधन समिति द्वारा पुष्पगुच्छ, शाल, श्रीफल एवं प्रतीक चिन्ह भेंटकर स्वागत किया गया।वार्षिकोत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों ने सरस्वती वंदना, योगासन एवं विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रभावी प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, खेल एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को मेडल, ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

पत्रकारवार्ता

नए आपराधिक कानूनों से पुलिस प्रक्रिया हुई आसान: विजय शर्मा

रायपुर। उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने आज गृह एवं जेल विभाग की उपलब्धियों के संबंध में नया रायपुर स्थित संवाद ऑडिटोरियम में पत्रकारों से चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार बनने के साथ ही हम एक नई सोच को लेकर कार्य कर रहे हैं। राज्य की क्षमता में विस्तार के लिए नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन अन्तर्गत आइसीजेएस के तहत पांचों स्तंभों पुलिस, अभियोजन, फारेंसिक, जेल एवं न्यायालय को एकीकृत करने की प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ राज्य अग्रणी है। दुर्ग एवं बिलासपुर जिले पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर पांचों पिलर्स को एकीकृत कर एक मॉडल जिले के रूप में उभर कर सामने आये हैं। पहले पुलिस को साक्ष्यों को लेकर कई बार समास्याओं का सामना करना पड़ता था अब ई- साक्ष्य के आने से तुरंत साक्ष्य उपलब्ध हो रहे हैं।

जिससे पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ा है।

गृह मंत्री श्री शर्मा ने बताया कि पुलिस कार्यों के आधुनिकीकरण के लिए सीसीटीएनएस द्वारा मेडलीपार, ई- साक्ष्य, ई -सम्मन, ऑनलाइन एफआईआर, ई- साइन, ई- कोर्ट, ई- श्रुति के द्वारा कार्यों को त्वरित और आसान बनाया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को न्याय प्राप्ति में आसानी होगी। पुलिस कर्मियों के लिए अब तक किसी प्रकार की बीमा की व्यवस्था नहीं थी, जिस पर ध्यान देते हुए सरकार द्वारा 08 बैंकों के साथ एमओयू कर बिना किसी प्रीमियम के सैलरी अकाउंट पर बीमा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, इसका लाभ छत्तीसगढ़ पुलिस के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्राप्त हो रहा है। यह पुलिस कर्मियों के लिये कल्याणकारी योजनाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब तक 15 शहीद पुलिसकर्मियों के आश्रितों को 16 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। गृह मंत्री ने बताया कि पहले अपराध समीक्षा हाथ से लिखकर उपलब्ध कराया जाता था जो पुलिस विवेचना में देरी होती थी, अब राज्य की अभिनव पहल के रूप में अपराध समीक्षा एप्लीकेशन से पूरे राज्य में दर्ज एफआईआर की निगरानी, समीक्षा एवं विश्लेषण की जा रही है। जहां समय-सीमा में अपराधों का विवेचना के साथ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप इसका पर्यवेक्षण किया जा रहा है जिससे जवाबदेहिता सुनिश्चित हो रही है और हर स्तर पर उसकी निगरानी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु ऑनलाइन कम्पलेंट मैंनेजमेंट पोर्टल का निर्माण किया गया है। पूर्व में शिकायतों को संबंधित जिलों में डाक के माध्यम से प्रेषित किया जाता था और जिलों के द्वारा भी संबंधित शिकायतों का जांच प्रतिवेदन डाक के माध्यम से ही मुख्यालय को प्राप्त होता था।

4 बड़े बकायेदारों के 6 व्यावसायिक परिसरों पर ताला, सीलबंदी कार्रवाई

रायपुर। बकाया राजस्व की वसूली को लेकर रायपुर नगर निगम ने कड़ा रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम के जोन राजस्व विभाग ने बकाया राशि अदा नहीं करने वाले चार बड़े बकायेदारों के छह व्यावसायिक परिसरों को तत्काल प्रभाव से ताला लगाकर सीलबंद कर दिया। इस कार्रवाई से बकायेदारों में हड़कंप की स्थिति देखी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह सख्त कदम नगर निगम आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर उठाया गया। आयुक्त के आदेशानुसार अपर आयुक्त राजस्व कृष्णा खटीक, उपायुक्त राजस्व जागृति साहू तथा जोन 10 के जोन कमिश्नर विवेकानंद दुबे के मार्गदर्शन में जोन राजस्व टीम ने

यह कार्रवाई की। नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि संबंधित बकायेदारों को पूर्व में कई बार नोटिस जारी कर बकाया राशि जमा करने के लिए कहा गया था।

निर्धारित समयावधि में भुगतान नहीं किए जाने पर निगम ने सीलबंदी की कार्रवाई की। अधिकारियों के अनुसार, निगम प्रशासन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि राजस्व वसूली के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कार्रवाई जिन बकायेदारों के विरुद्ध की गई, उनमें ज्योति केशवानी, केवलराम केशवानी, भरत कुमार प्रिथवानी तथा रेखा लाल- एल. के. लाल शामिल हैं।

नगर निगम प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में भी बकाया करों एवं शुल्कों की वसूली के लिए अभियान जारी रहेगा। निगम अधिकारियों ने सभी बकायेदारों से अपील की है कि वे समय पर अपने बकाया का भुगतान करें, ताकि इस प्रकार की कठोर कार्रवाई से बचा जा सके। निगम का कहना है कि शहर के विकास कार्यों और नागरिक सुविधाओं के लिए राजस्व की नियमित वसूली अत्यंत आवश्यक है।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.